A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 11 जून, 2026
इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 11 अंक 249, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

एआई : भारतीय कॉपीराइट कानून को भी अब बदलना होगा

मीनाक्षी लेखी

क्या AI या Open AI का उसकी मदद से बने क्रिएशन से हुई कमाई, आय या इनकम में कोई हिस्सा होता है? AI इस म्यूज़िक के परफॉर्मेंस से होने वाले प्रॉफिट का कितना हिस्सा क्लेम कर सकता है? यह सवाल उन किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिनमें प्रेरणा, आइडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और कहानी की रूपरेखा बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है। यह लेखकत्व, स्वामित्व और नैतिकता के इर्द-गिर्द एक बड़ी बहस को जन्म देता है, और हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में संपन्न हुए राष्ट्रीय सम्मेलन, 'ऑथरलेस होराइजन्सः AI, ऑथरशिप, और उभरता हुआ क्रिएटिव इकोसिस्टम' में चर्चा किए गए मुद्दों में से एक था।

'ऑथरशिप, ओनरशिप और एथिक्सः AI के ज़माने में लीगल चैलेंज' टाइटल वाले एक कॉन्क्लेव सेशन में, जाने-माने लेखक, स्कॉलर और एकेडेमिक्स एक साथ आए और AI और उसके टूल्स पर डिपेंडेंस बढ़ने से पैदा होने वाली कई एथिकल और मोरल मुश्किलों पर बात की। एकेडेमिक्स इस बात पर बहस करते हैं कि क्या AI से बने काम को एनालाइज़ करने और उसे इस तरह मार्क करने के कोई पक्के तरीके हैं। कुछ कॉलेज प्रोफेसरों का कहना है कि स्टूडेंट्स के काम, जैसे रिसर्च पेपर और डिजर्टेशन, को टर्निटिन जैसे AI-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से गुज़ारा जाना चाहिए। अगर AI का इस्तेमाल पकड़ा जाता है, तो स्टूडेंट को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, जिसमें सस्पेंशन, एकेडमिक प्रोबेशन, F ग्रेड और सबसे गंभीर मामलों में, नौकरी से निकालना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्टूडेंट्स मज़बूत और इनोवेटिव होते हैं और टेक्नोलॉजी अक्सर युवा दिमाग की काबिलियत के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती।

कई वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ने यह पॉलिसी अपनाई है, 'अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उनके साथ जुड़ जाइए', यह समझते हुए कि AI सुनामी के हमले से लड़ना बेकार है। बल्कि, वे अब स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट और एकेडमिक काम पूरा करने के लिए एंथ्रोपिक के क्लाउड, ओपन AI के चैट GPT, या पर्प्लेक्सिटी AI जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करने पर सज़ा नहीं दे रहे हैं। सच तो यह है कि यह पक्का पता लगाने का कोई पक्का तरीका नहीं है कि एकेडमिक, लिटरेरी, या लिखा हुआ काम AI से बना है या नहीं।

भारत में भी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने डॉक्टोरल रिसर्च में प्लेजरिज्म और AI टूल्स के इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं, जिसमें बिना ओरिजिनल काम के लिए पेनल्टी और सुपरवाइजर की ज़्यादा ज़िम्मेदारी तय की गई है, लेकिन यह कोई सीधा मामला नहीं है। पीएचडी थीसिस और रिसर्च पेपर अक्सर पब्लिक सर्वर पर डाल दिए जाते हैं ताकि दूसरे स्कॉलर उन्हें एक्सेस कर सकें। यही खुलापन उन्हें बिना साफ सहमति या क्रेडिट के AI द्वारा माइन किए जाने का खतरा भी बनाता है।

लिंग्विस्ट अक्सर दावा करते हैं कि ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल (LLM) की मदद से तैयार किए गए साहित्यिक काम की पहचान करना आसान है। इस साल मशहूर कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आरोप लगे कि पांच क्षेत्रीय विजेताओं में से तीन की कहानियां संभवतः LLM की मदद से तैयार की गई थीं। याद रखना ज़रूरी है कि भारत में, पाणिनी की अष्टाध्यायी ने संस्कृत ग्रामर के साइंस को लगभग 4,000 सूत्रों में बहुत ही सटीक तरीके से बताया था, यह तब की बात है, जब मॉडर्न मशीनें भाषा को प्रोसेस और बना नहीं पाई थीं। यह दुख की बात होगी अगर यह इंटेलेक्चुअल विरासत पूरी तरह से AI को सौंप दी जाए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, AI पर पूरी तरह से डिपेंड रहना एक फिसलन भरी ढलान बन सकता है। इसलिए, इंडिजिनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपस्किलिंग और इस तरह के डिपेंडेंस से आम लोगों पर पड़ने वाले डंबिंग-डाउन असर पर पूरा ध्यान देना होगा।

क्रिएटिव फील्ड में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से कई कानूनी और नैतिक सवाल उठते हैं, जैसे कि AI से बने कंटेंट का मालिक कौन है, क्या कॉपीराइट वाले मटीरियल का इस्तेमाल बिना इजाज़त के AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है और क्या यूज़र्स को AI से उनकी इजाज़त के बिना खास क्रिएटर्स या ब्रांड्स के काम की नकल करने के लिए कहने की इजाज़त होनी चाहिए।

आज, पब्लिक पर्सनैलिटीज़ के ओरिजिनल कंटेंट, जिसमें भाषण, आर्टिकल और पब्लिक डोमेन में मौजूद पब्लिश किए गए काम शामिल हैं, को AI द्वारा बहुत आसानी से कॉपी किया जा सकता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां एक्टर, पॉलिटिशियन और यहां तक कि आम लोगों की असली तस्वीरों की जगह AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी, डीपफेक, भले ही मशीन से बनाए गए हों, असल ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी अपनी डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए कोर्ट गए हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 आज के AI माहौल के साथ चल पाया है या नहीं, यह एक फॉलो-अप आर्टिकल और गहरी कानूनी स्टडी का टॉपिक है। हालांकि, यह खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग से पूरी तरह से बने कंटेंट के मालिकाना हक के बारे में नहीं बताता है।

भारत में कॉपीराइट प्रोटेक्शन आम तौर पर इंसान के हाथ से लिखने पर आधारित है और एक्ट लेखकों को ऐसे आम लोगों के तौर पर पहचानता है जो ओरिजिनल साहित्यिक, म्यूज़िकल या ड्रामा का काम करते हैं। नतीजतन, पूरी तरह से AI से बने कंटेंट को कॉपीराइट प्रोटेक्शन और मालिकाना हक को लेकर शक वाली उलझन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई इंसान AI से बने मटीरियल को बनाने, चुनने, एडिट करने या अरेंज करने में काफी क्रिएटिव इनपुट देता है, तो कॉपीराइट इंसानों के बनाए एलिमेंट्स में भी बना रह सकता है – कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 2(d)(vi) कंप्यूटर से बने काम के लेखक को वह व्यक्ति मानता है जो उस काम को बनवाता है, हालांकि, इसमें AI को शामिल नहीं किया गया है।

AI के इंसानी समाज में फैलने और पैठ से उठने वाले ऐसे मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए भारत में कानूनी ढांचे को बदलने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट वाले कामों को दोबारा बनाना और स्टोर करना कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 51 के तहत जांच का विषय बन सकता है, जो कॉपीराइट उल्लंघन के लिए खास कामों को तय करता है। यह भी सवाल उठ सकते हैं कि क्या AI से बना कंटेंट एक बदलाव लाने वाला क्रिएशन है या मौजूदा कामों का गलत तरीके से दोबारा बनाना है। यह भारतीय कानून बनाने वालों के लिए एक ज़रूरी सवाल है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

पीएम मोदी के राष्ट्रीय सेवा के बारह वर्ष पूर्ण, देशवासियों के लिए गौरवशाली क्षण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक अवधि तक देशसेवा करने का रिकॉर्ड आज अपने नाम किया है। वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया है। यह सभी देशवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी, जनता के हित में एकजुटता के साथ कार्य करते हैं। वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भारत को दुनिया में नंबर-1 देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

- **प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के भीतर जनसेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा सशक्त हुई है–** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, बेटियां सुरक्षित थीं, गौमाता के पूजन के साथ-साथ सनातन संस्कृति के मंदिरों का वैभव था। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यकाल भी इन्हीं उपलब्धियों का साक्षी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी सादगीपूर्ण जीवनशैली के साथ देश सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को मकान दिलवाए, 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क अनाज वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के भीतर जनसेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा सशक्त हुई है।
- **हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं–** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। देश-दुनिया से श्रद्धालु मंदिर में प्रभु श्रीराम और हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रभु श्रीराम की विशेष कृपा मध्यप्रदेश पर है, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है।
- **प्रधानमंत्री का मध्यप्रदेश को लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है–** स्थानीय सांसद श्री आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने विगत वर्षों में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता, डिजीटल नवाचार और इन्फ्रास्ट्रक्टर निर्माण में अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन में गरीब, किसान, नारी सशक्तिकरण और युवाओं के गहरी संवेदना हैं। मध्यप्रदेश को हर पल उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है।

देश में एक नए संकल्प का वातावरण है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगवान श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी पवित्र गीता में बताए कर्मवाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। उन्होंने अपने कार्यों से पृथ्वी पर अपने जन्म को सार्थक किया है। गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री श्री मोदी आज देश के गरीब परिवारों के लिए एक आदर्श हैं। देश में एक नए संकल्प का वातावरण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सबको अवसर मिलता है। प्रदेशवासी अपने जीवन में संकल्प लें, संघर्ष करें और आगे बढ़ें।

12 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने लिए ताबड़तोड़ फैसले

- आंध्र की राजधानी अमरावती को दिया 2,534 करोड़ रुपए का गिफ्ट
- अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2ए को भी कैबिनेट की मिल गई है मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4,703 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें से दो परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से जुड़ी हैं जिनकी कुल लागत करीब 2,500 करोड़ रुपये है। साथ ही एक प्रोजेक्ट अहमदाबाद में मेट्रो से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो की फेज 2ए को मंजूरी दे दी है। अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं। फेज 2ए के तहत कोटेश्वर रोड से सरदार वल्लभभाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच मेट्रो लाइन बनाई जाएगी।

पीएम मोदी बोले– कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, एक दिन देशवासी मेड इन इंडिया प्लेन में सफर करेंगे

पीएम मोदी ने भारत मंडपम में देशभर से आए एनडीए नेताओं को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित एनडीए बैठक में उनका सम्मान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 12 साल में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। इस कुसंस्कृति का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट था। इसमें न गवर्नेंस थी, न नीति, न नीयत और न ही निर्णय। नाकामी कांग्रेस की थी लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया गया। पीएम ने कहा, हमारे लिए दल से बड़ा हमेशा देश रहा है। हम नेशन फर्स्ट की भावना से काम करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम मेड इन इंडिया प्लेन भी बनाएंगे।

सुप्रभात

चढ़ी जो धूप तो इक-इक
शजर की याद आई
नए सफ़र में पुराने सफ़र
की याद आई
उधर गए तो इधर की कमी
हुई महसूस
इधर जो आए तो हर पल
उधर की याद आई
हर एक लफ़्ज़ का हर
हर्फ़ भीग-भीग गया
जो तेरे ख़त से तिरी
चश्म-ए-तर की याद आई
हर अजनबी में शनासा
तलाश करते रहे
पराए देस में जब अपने
घर की याद आई
वो और थे जिन्हें याद
आया दश्त में दरिया
हमें तो दश्त में दीवार-ओ-दर
की याद आई
भुला ही बैठा था दानों के
फेर में सब कुछ
क़फ़स में जाके परिंदे को
पर की याद आई

- **राजेश रेड्डी**

मोदी सरकार के 4399 दिन

टूटा नेहरू का रिकॉर्ड

- **पूरी कैबिनेट ने तालियां बजाकर किया मोदी का स्वागत**

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। पीएम के तौर पर यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास था। वे 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद 4398 दिनों तक इस पद रहे। दोपहर 12.30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाई। साथ ही एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया।

अब चीन-पाकिस्तान से इकट्ठे निपटेगी सेना

- भारतीय सेना ने तैयार किया युद्ध का ब्लू प्रिंट
- भारत के तीन शहरों में थियेटर कमांड की चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेनाओं के लिए थियेटर कमांड वाले आइडिया को अमलीजामा पहनाने के काम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। यूं तो यह आइडिया करीब 6 साल पुराना है, लेकिन अपना कार्यकाल खत्म होते-होते पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसका एक ठोस खाका तैयार कर दिया है, जिसे ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। अब रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को इसपर निर्णायक फैसला लेना है। भारतीय सशस्त्र सेना को थियेटर कमांड से जोड़ने की खबरों के बीच साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार अभी भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी जो कुल 17 कमांड में काम करती है, वह ढांचा सिमट कर मात्र तीन थियेटर कमांड के अधीन लाया जाना है।

तीन शहरों में थियेटर कमांड–रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थर्न थियेटर कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। नॉर्थर्न थियेटर कमांड का पूरा फोकस चीन पर होगा। नॉर्थर्न थियेटर कमांड की अगुवाई मुख्य तौर पर आर्मी के हाथों में होगी। वेस्टर्न थियेटर कमांड जयपुर से संचालित होगा और इसके पास पाकिस्तान से निपटने की जिम्मेदारी होगी।

पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आइडिया

भारत में तीनों सेनाओं को थियेटर कमांड से जोड़ने का आइडिया औपचारिक तौर पर पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दिया था। उन्होंने 6 साल पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। वे शीर्ष जनरलों, एडमिरलों और एयर चीफ मार्शलों के जरिए सशस्त्र सेनाओं के काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे और सेनाओं के बीच पूर्ण ऑपरेशनल सिनर्जी चाहते थे।

- **ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बढ़ गई जरूरत–** ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन की ओर से पाकिस्तान की सक्रिय मदद की बातें सामने आई हैं, उसके बाद से थियेटर कमांड की जरूरत काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान की पहल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य थियेटर की तर्ज पर ही तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने की कोशिशें भी हुईं और उसमें सफलता भी मिली। एक डिफेंस थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के एक रिसर्चर गौरव कुमार ने एससीएमपी से कहा, भारत में चिंता अभी ये है कि मिलिट्री के पास एक बार में एक ही चुनौती से निपटने जैसी सुविधा अब न रह जाए। पहले चीन और पाकिस्तान को मोटे तौर पर भिन्न सुरक्षा समस्या की तौर पर देखा जाता था।
- **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई ब्लूप्रिंट–** इससे पहले रिपोर्ट दी थी कि पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार्यकाल की समाप्ति से पहले थियेटर कमांड का एक पुख्ता ब्लूप्रिंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा है। इस ब्लूप्रिंट में थियेटर कमांड का स्ट्रक्चर, ह्यूमैन रिसोर्सेज, सिनर्जी मेकेनिज्म और एसओपी की जानकारी दी है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 11 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 40 लाख मतदाता बढ़े

● 1.41 करोड़ नाम हटे, यूपी में हर वोटर को मिला 9 अंकों का खास नंबर

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची बुधवार को जारी कर दी गई। तमाम दावों, आपत्तियों के निस्तारण और गहन सत्यापन के बाद इस फाइनल लिस्ट को तैयार किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार एक बड़ा बदलाव करते हुए हर पंचायत मतदाता को 9 अंकों का एक यूनिक पहचान नंबर जारी किया है। हालांकि, सूची जारी होते ही कई जिलों में वोटर्स को

इसे डाउनलोड करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, ऐसा तकनीकी दिक्कतों के चलते हो रहा है। **1.81 करोड़ नए नाम जुड़े, 1.41 करोड़ हटे**-राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले 18 दिसंबर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसके बाद चले संशोधन अभियान के बाद आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 1.81 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। वहीं, करीब 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 40.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बिहार में कोचिंग बिल लाने की शुरू हुई तैयारी

● सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, स्कूल-कॉलेजों के समय नहीं होगी कोचिंग की अनुमति

पटना (एएजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब राज्य का कोई

भी कोचिंग संस्थान स्कूल और कॉलेज के तय समय के दौरान अपनी कक्षाएं नहीं चला सकेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अपनी मुख्य स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कोचिंग न जाएं। दरअसल, पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों को चलाने वालों (खान सर और रोशन आनंद) के बीच विवाद के चलते सरकार को इस बारे में फैसला लेना पड़ा। राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

पेट्रोल-सिलेंडर के बाद अब 'फ्लाइट' की बारी

टिकट के भी बढ़ेंगे दाम, जेट फ्यूल हुआ महंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार की नई प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत, घरेलू एयरलाइंस अब तीन साल तक के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें तय कर सकती हैं। साथ ही सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने जेट फ्यूल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। नई व्यवस्था के तहत, जो एयरलाइंस इस स्वैच्छिक योजना को चुनेंगी उन्हें एटीएफ के लिए 115 रुपये प्रति लीटर की तय कीमत चुकानी होगी। पहले ये कीमत 104.927 रुपये प्रति लीटर थी। जो एयरलाइंस इस फ्रेमवर्क से बाहर रहने का फैसला करती हैं, वे मार्केट से जुड़े रेट पर ही फ्यूल खरीदती रहेंगी। ये रेट अभी लगभग 142 रुपये प्रति लीटर हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा चुकाई जाने वाली

कीमतों के बराबर हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह स्कीम पूरी तरह से ऑप्शनल है और एयरलाइंस खुद तय करेंगी कि वे इसमें शामिल होना चाहती हैं या नहीं। जो एयरलाइंस इसमें शामिल होंगी वे लॉक-इन पीरियड के दौरान इंटरनेशनल बेंचमार्क कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहेंगी। वहीं, जो एयरलाइंस इसमें शामिल नहीं होंगी उन्हें कीमतें घटने पर तो फायदा हो सकता है लेकिन कीमतें बढ़ने पर उसका बोझ भी उन्हें ही उठाना होगा।

वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ीं

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इस साल की शुरुआत में वेस्ट एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद ग्लोबल फ्यूल की कीमतें बढ़ने के बावजूद, दिल्ली में घरेलू सीएनजी की कीमतें दो महीने से ज्यादा समय तक लगभग 105 रुपये प्रति लीटर पर बनी रहीं। खबरों के मुताबिक, इंटरनेशनल कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ बोझ ही ग्राहकों पर डालने की वजह से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था। इन नुकसानों की भरपाई करने और एविएशन सेक्टर को भविष्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये के प्राइस स्टेबलाइजेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इस सिस्टम के तहत अगर ग्लोबल बेंचमार्क कीमतें 86.32 रुपये प्रति लीटर के बेस रेट से ऊपर जाती हैं तो सरकार इस अंतर को पाटने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बिना ब्याज के एडवांस देगी। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम होंगी तो अतिरिक्त रकम वसूल कर भारत के कंसोलिडेटेड फंड में वापस जमा कर दी जाएगी।

किसानों के अनाज से बनाई पीएम मोदी की रंगोली

विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने और सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर भोपाल के नीलबड़ में विशेष आयोजन किया गया। यहां किसानों के अनाज से प्रधानमंत्री मोदी की आकर्षक रंगोली बनाई गई।

यह आयोजन भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की पहल पर नीलबड़ स्थित दुर्गा माता मंदिर परिसर में हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया।

अनाज से बनाई गई रंगोली- रामेश्वर शर्मा ने बताया कि रंगोली किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज से बनाई गई है। रंगोली में प्रधानमंत्री के 12 सालों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

पीएम के दीर्घायु की कामना- कार्यक्रम में किसानों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके बाद मां सिंहवाहिनी मंदिर में आरती कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, किसान और क्षेत्र के सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे।

पौधरोपण भी किया

इधर, भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्मृति कल्प का आयोजन इंदौर में जून को

इंदौर। प्रख्यात कथाकार, पद्मश्री से अलंकृत, श्रीमति मालती जोशी की स्मृति में होने वाला वार्षिक आयोजन 'स्मृति कल्प' इस बार रविवार 14 जून को प्रीतम लाल दुआ सभागार इंदौर में सुबह दस बजे से होगा। आयोजन में दो सत्र होंगे जिनमें मालती जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा चर्चा की जाएगी तथा उनकी कहानियों का पाठ होगा। इसमें शिरकत करने इस वर्ष प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता, पटकथाकार और निर्देशक अतुल तिवारी मुंबई से और, वरिष्ठ साहित्यकार और संपादक लक्ष्मीशंकर बाजपेयी दिल्ली से आ रहे हैं। जानी मानी टेलीविजन हस्ती और साहित्यकार रंजना चितले और प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर तथा रंगमंच हस्ती मंजूषा राजस जौहरी, मालती जी की कहानियों का पाठ करेंगी। प्रसिद्ध साहित्यकार ज्योति जैन, अनीता सक्सेना और शिक्षा विद मधुरा फड़के अपने संस्मरण साझा करेंगी। यह आयोजन सोमनाथ एंड मालती जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई

विगत 5 दिनों में लगभग 1 करोड़ 62 लाख रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त, अनेक तस्कर गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विगत 5 दिनों में विभिन्न जिलों की पुलिस ने अलग-अलग मामलों में त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 62 लाख रूपये से अधिक के अवैध मादक पदार्थ गांजा, स्मैक, एमडी ड्रग्स, डोडाचूरा, नशीले इंजेक्शन सहित अन्य सामग्री जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आगर मालवा-कोतवाली थाना पुलिस ने कंटेनर में बनाए गए विशेष लोहे के गुप्त चैम्बर से 3 क्विंटल 21 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में लगभग 71 लाख रुपये मूल्य का डोडाचूरा एवं कंटेनर जब्त किया गया।

शिवपुरी-पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को स्मैक का अवैध विक्रय करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62.28 ग्राम स्मैक, एक कार एवं मोबाइल फोन सहित लगभग 22 लाख मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

मंदसौर-मल्हारगढ़ पुलिस ने बोलेरो वाहन में बनाए गए गुप्त स्थानों से 173 किलो 380 ग्राम डोडाचूरा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अन्य कार्रवाई में 400 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए। वहीं शामगढ़ पुलिस ने हरियाणा

एवं पंजाब के दो तस्करों को गिरफ्तार कर 60 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया। इस प्रकार तीनों कार्रवाई में मंदसौर पुलिस ने लगभग 17 लाख 66 हजार रुपये मूल्य का मादक पदार्थ एवं अन्य संपत्ति जब्त की है।

उज्जैन-पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध दो अलग-अलग कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने 1 किलो 15 ग्राम एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लगभग 15 लाख रूपये की सामग्री जब्त की है।

इलाज कराने पहुंची युवती से छेड़छाड़

आरोपी झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार, चेकअप के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप

भोपाल (नप्र)। भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में इलाज कराने पहुंची एक 18 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि चेकअप के दौरान डॉक्टर ने युवती को गलत नीयत से छुआ। युवती ने विरोध करते हुए शोर मचाया और क्लीनिक से बाहर आकर परिजनों को पूरी घटना बताई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, युवती सूखी सेवनिया क्षेत्र के एक गांव में रहती है। पिछले करीब 8 से 10 दिन से उसे सिर दर्द की शिकायत थी। इलाज के लिए वह गांव में क्लीनिक चलाने वाले संजीत कुमार बंगाली के पास पहुंची थी।

अश्लील हरकतें देख पीड़िता ने शोर किया- युवती का आरोप है कि इलाज और चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और बुरी नीयत से छुआ। युवती को जब डॉक्टर की हरकत का एहसास हुआ तो उसने विरोध किया और शोर मचाते हुए क्लीनिक से बाहर आ गई।

क्लीनिक से बाहर आने के बाद युवती ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के साथ मारपीट की और थाने पहुंचकर आरोपी को पुलिस के हवाले करने के बाद एफआईआर दर्ज करा दी।

विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की चर्चा !

● एकजुटता दिखाने दिल्ली पहुंचे यूपी एनडीए के सहयोगी

लखनऊ (एजेंसी)। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी एकजुटता दिखाने की तैयारी में हैं। यूपी से एनडीए के सभी सहयोगी शामिल होंगे, जिनमें अपना दल (एस) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर,निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी शामिल हैं। ओपी राजभर और संजय निषाद मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए, वहीं जयंत ने एनडीए के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने सभी दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसमें बुधवार को शामली में होने वाली रैली भी शामिल थी। नई दिल्ली स्थित

भारत मंडपम में 10 जून, 2026 को एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न बनाया जा रहा है। **भारत ने वैश्विक मंच पर बनाई नई पहचान: ओपी राजभर-** राजभर ने कहा कि पिछले 12 सालों में एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय विकास, गरीबों के कल्याण, सामाजिक न्याय, बुनियादी ढांचे और किसानों, युवाओं व महिलाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किया है।

● **सरकार की नीतियों का फायदा आखिरी व्यक्ति तक :संजय निषाद-** वहीं, संजय निषाद ने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियों और योजनाओं का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने का काम किया है।

● **यूपी चुनाव से पहले सहयोगियों की एकजुटता अहम-** गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए सहयोगियों का एकजुटता दिखाना बहुत अहम है क्योंकि यहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक, सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाकर भाजपा का मकसद इस धारणा को खत्म करना है कि सिर्फ विपक्ष ही एकजुटता दिखा रहा है।

भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस-मेटा

● गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा, क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मेटा भारत में अपना पहला एआई-इनेबल्ड डेटा सेंटर बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी कर रही है। इस पार्टनरशिप के तहत गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा, जिसे दो साल के भीतर डिलीवर करने का लक्ष्य है। इस साझेदारी के तहत रिलायंस जामनगर में डेटा सेंटर को पूरी तरह से विकसित करेगी। रिलायंस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल पावर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और मैनेज्ड सर्विसेज सहित एंड-टू-एंड सर्विसेज देगी।

भारत वैश्विक एआई क्रांति में सबसे आगे रहने को तैयार- रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा,मेटा के साथ यह साझेदारी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बदलावकारी पल है। मेटा का भारत का पहला बिल्ट-टू-सूट डेटा सेंटर बनाना यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक एआई क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए तैयार है। जामनगर हाइपरस्केल एआई कंप्यूटिंग के लिए एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन बनेगा। मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी पुष्टि की है।

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और 'मेटा कंप्यूट' पर भारी निवेश

मेटा अपनी बढ़ती एआई जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर निवेश कर रही है। जुकरबर्ग ने मेटा कंप्यूट नामक एक टॉप-लेवल पहल के जरिए इस दशक में डिकेड्स ऑफ गीगावाट और आगे चलकर हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट या उससे ज्यादा क्षमता बनाने का प्लान बनाया है। जनवरी 2026 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की पूर्व सलाहकार दीना पॉवेल मैकॉर्मिक को प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया, जो सरकारों के साथ मिलकर मेटा के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग पर फोकस कर रही हैं। अप्रैल में मेटा ने अपने पूरे साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के अनुमान को 115-135 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 125 बिलियन डॉलर से 145 बिलियन डॉलर कर दिया है।

बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में ईरान का हमला

● अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइलें, जवाब में कार्रवाई

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान ने बुधवार को बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कुल 21 हमले करने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नुकसान की जानकारी बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इससे पहले सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। एक दिन बाद ट्रम्प ने इसका आरोप ईरान पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस हमले का जवाब जरूर देगा और इसके जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट एलिजाह मैग्नियर का कहना है कि लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों लंबे युद्ध से बचना चाहते हैं।

'ब्रिक्स' सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी प्रतिनिधियों ने बुधवार सुबह ढक्कन वाले कुएं स्थित ग्रामीण हाट बाजार का दौरा किया। यहां प्रदेश की कृषि,जैविक उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को करीब से देखने का अवसर मिला। हाट बाजार पहुंचने पर विदेशी प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। प्रवेश द्वार पर लोक कलाकारों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुति दी। लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखकर कई विदेशी मेहमान भी कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य करते नजर आए। यह दृश्य आयोजन का सबसे यादगार पल बन गया। जिला प्रशासन,आत्मा परियोजना और कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित यह प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विदेशी मेहमानों ने विभिन्न प्रकार के अनाज,मोटे अनाज (श्री अन्न) तथा कृषि उत्पादों की जानकारी ली और किसानों से संवाद भी किया। हाट बाजार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान उत्पादकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहां केले के फाइबर से बने वस्त्र,जैविक फल-सब्जियां, ए-2 दूध एवं डेयरी उत्पाद,प्राकृतिक शहद,गोबर से निर्मित पर्यावरण-अनुकूल सामग्री,पैशन फ्रूट उत्पाद तथा डीहाइड्रेटेड फल और सब्जियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प और वस्त्र परंपरा भी यहां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

फर्जी अपर कलेक्टर बनकर ढाई लाख ठगे

इंदौर। जिला न्यायालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत रुपेश जोशी ने खुद के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर

जनसुनवाई में दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि एक युवती ने स्वयं को अपर कलेक्टर बताकर जमीन नामांतरण कराने का झांसा दिया और उससे करीब ढाई लाख रुपये ले लिए। रुपेश जोशी के अनुसार यह घटना करीब तीन वर्ष पहले की है। रकम लेने के बावजूद न तो जमीन का नामांतरण हुआ और न ही पैसे लौटाए गए। मामले में उन्होंने पहले लसूड़िया थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर जनसुनवाई का सहारा लिया। जनसुनवाई में शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों ने लसूड़िया थाना पुलिस को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पड़ोसी दुकानदार ही निकला चोर

इंदौर। शहर के व्यस्ततम नावेल्टी मार्केट में हुई चोरी की वारदात का एमजी रोड पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हैरानी की बात यह रही कि चोरी किसी बाहरी बदमाश ने नहीं, बल्कि पीड़ित की दुकान के सामने कारोबार करने वाले दुकानदार ने ही अंजाम दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 1 लाख 23 हजार 340 रुपए की नगदी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, सुमित कलेक्शन के संचालक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 जून की रात दुकान बंद कर घर जाने के बाद अगले दिन सुबह दुकान का ताला टूटा मिला और गल्ले में रखी नकदी गायब थी। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पीड़ित की दुकान के सामने दुकान संचालित करने वाला अंश चंदवानी संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की अधिकांश रकम बरामद कर ली है। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

जीजा-साले पर चौकीदार का हमला

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर-78 में एक खाली प्लॉट पर लघुशंका करने गए जीजा-साले पर चौकीदार और उसके साथियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फरियादी मानसिंह राठौर अपने साले उत्तम सिंह के साथ देर रात इलाके के एक खाली प्लॉट पर गए थे। इसी दौरान पास में बनी झोपड़ी से एक चौकीदार बाहर आया और वहां लघुशंका करने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब दोनों ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि चौकीदार झोपड़ी से लाठी लेकर आया और मानसिंह पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में दोनों थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चौकीदार और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

फर्जी हस्ताक्षर से वाहन छुड़ाने पहुंचा

इंदौर। जब्त वाहन को सुपुर्दगी में लेने के लिए फर्जी दस्तावेज और नकली हस्ताक्षरों का सहारा लेने वाले एक आरोपी के खिलाफ एमजी रोड पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने खुद को वाहन का असली मालिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर जगजीवन राम नगर निवासी अनिल सिसोदिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने कोर्ट में वाहन के वास्तविक स्वामी शिवनारायण गौर बनकर सुपुर्दनामा आवेदन प्रस्तुत किया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर किए। पहचान के लिए असली मालिक का आधार कार्ड भी संलग्न किया गया था। हालांकि, कोर्ट की सतर्कता के चलते दस्तावेजों की जांच में मामला पकड़ में आ गया और आरोपी वाहन छुड़ाने में सफल नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

3 लाख, दस्तावेजों से भरा बैग बरामद

इंदौर। दिल्ली से इंदौर आए सेनेटरी व्यापारी के लिए उस समय परेशानी खड़ी हो गई, जब व्यापारियों से वसूली रकम और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग कहीं गुम हो गया। पुलिस ने दो घंटे के भीतर बैग खोजकर सुरक्षित वापस कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी राहुल मित्तल को व्यापारिक भुगतान लेने इंदौर आए थे। उन्होंने सियागंज के व्यापारियों से पैसे लेने के बाद ई-रिक्शा के माध्यम से सिंधी कॉलोनी की ओर प्रस्थान किया। सिंधी कॉलोनी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका बैग रास्ते में कहीं गिर गया है। बैग में 3 लाख रुपए नकद के साथ कई दस्तावेज भी रखे थे। बैग गुम होने की जानकारी मिलते ही राहुल ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रावजी बाजार और उनकी टीम ने तत्काल जांच शुरू की। व्यापारी द्वारा बताए मार्ग के विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की मदद से बैग की तलाश शुरू की गई। पुलिस की सक्रियता रंग लाई और कुछ ही घंटों में बैग को खोज निकाला। जांच के दौरान बैग में रखी नकदी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित मिले।

दोपहिया वाहन में 12 बोतल व्हिस्की

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। विभाग द्वारा माह में कई कार्रवाइयां की जाती है। इसी क्रम में राजमोहल्ला वृत्त में आबकारी विभाग ने दोपहिया वाहन को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक, मालवा हॉस्पिटल जैन मंदिर 60 फीट रोड पर कार्रवाई की। यहां से वाहन क्रमांक एमपी-09-एक्सएम-1662 को रोका और चेक किया। बाइक के बैग से 12 बोतल व्हिस्की जब्त की।

30 साल की नौकरी में धन कुबेर बने जेडी के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा

लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 241% अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा

इंदौर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन की इंदौर इकाई ने बुधवार सुबह महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मीनारायण कंडवाल के आवास सहित उनसे जुड़े विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक डॉ राजेश सहाय को लक्ष्मीनारायण कंडवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। बुधवार सुबह लगभग 6 बजे से शुरू हुई कार्रवाई देर तक जारी रही। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अधिकारी तथा उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर इंदौर और धार जिले में बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति मौजूद है। इनमें कृषि भूमि, भूखंड और आवासीय भवन शामिल हैं। जांच के दौरान करीब 9.76 करोड़ रुपये के निवेश का पता चला, जबकि उनकी ज्ञात आय लगभग 2.80 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इतनी संपत्ति का ब्यौरा मिला - लोकायुक्त को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सोनवाय, जिला इंदौर में 0.097 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 6,64,170 रुपये का निवेश किया गया। वहीं धार जिले के ग्राम तारपुरा में सर्वे क्रमांक 33 की 2.560 हेक्टेयर कृषि

सराफा बाजार शाखा में एक लॉकर भी चिन्हित

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार आरोपी की संपत्ति उनकी वैध आय की तुलना में लगभग 241 प्रतिशत अधिक पाई गई है, जिसे अनुपातहीन संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। कार्रवाई के दौरान बैंक ऑफ इंडिया की सराफा बाजार शाखा में एक लॉकर भी चिन्हित किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। पूरे मामले की जांच के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें संपत्ति संबंधी दस्तावेजों, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत पड़ताल कर रही हैं। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भूमि 9,36,655 रुपये में खरीदी गई। इंदौर की स्कीम नंबर 103 स्थित आनंद विहार में भूखंड क्रमांक 149-सी खरीदने के साथ उस पर लगभग 13,560 वर्ग फीट क्षेत्र में जी+3 भवन का निर्माण कराया गया, जिस पर 2,66,57,450 रुपये खर्च होना पाया गया। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 140 में भूखंड क्रमांक 220 ए.एम. (54 वर्ग मीटर) पर 21,90,806 रुपये तथा उसी योजना के सेक्टर ए टाइप एम स्थित भूखंड क्रमांक 378 ए.एम. पर 15,34,572 रुपये का निवेश सामने आया है। जांच में धार जिले के ग्राम बनेडिया और बैकल्या सहित विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि की खरीद के कई मामले भी सामने आए हैं। ग्राम बनेडिया में 0.879 हेक्टेयर भूमि पर 12,26,118 रुपये, 1.176 हेक्टेयर भूमि पर 22,71,327 रुपये तथा 2.100 हेक्टेयर भूमि पर 40,55,940 रुपये खर्च किए गए। ग्राम तारपुरा, तहसील सागौर, जिला धार में 2.195 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 1,53,15,350 रुपये का निवेश मिला। वहीं तहसील पीथमपुर के ग्राम तारपुरा में 0.345 और 0.606 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 67,27,239 रुपये तथा 1.212 हेक्टेयर भूमि पर 25,00,000 रुपये व्यय किए गए। इसी तरह ग्राम बेकल्या, तहसील पीथमपुर में 1.740 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 11,94,185 रुपये, 2.435 हेक्टेयर भूमि पर 2,28,97,007 रुपये तथा एक अन्य 1.740 हेक्टेयर कृषि भूमि पर भी 11,94,185 रुपये का निवेश पाया गया। जांच में यह पूरा निवेश आरोपी, उनकी पत्नी, पुत्रों, पुत्रवधू और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज मिला है।

महाकाल चौपाटी विवाद गहराया दुकानदारों ने कोर्ट की शरण ली

35 से 40 लाख निवेश का दावा, व्यवसाय चलाने की मांग

इंदौर। भंवरकुआं क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित महाकाल चौपाटी को लेकर विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। चौपाटी में व्यवसाय संचालित कर रही अनीता ठाकुर सहित अन्य दुकानदारों ने जमीन मालिक पर दबाव बनाकर समय से पहले जगह खाली कराने का आरोप लगाया है।

पीड़ितों ने न्यायालय में याचिका दायर कर राहत की मांग की है। अनीता ठाकुर ने बताया कि उन्होंने 11 माह के एग्रीमेंट के आधार पर जमीन लेकर कैफे, जूस सेंटर सहित चार दुकानें स्थापित की हैं। चौपाटी निर्माण, बिजली व्यवस्था और अन्य संसाधनों पर करीब 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उनका दावा है कि जमीन मालिक को भी सीधे लगभग ढाई लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसके दस्तावेज उनके पास

मौजूद हैं। व्यवसायियों का आरोप है कि उन्हें लगातार जगह खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बुलडोजर चलाने और बिजली बंद करवाने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पीड़ितों का कहना है कि यदि एग्रीमेंट अवधि तक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो उनके निवेश की भरपाई कराई जाए। अधिवक्ता विनोद डांगी ने बताया कि जमीन मालिक को कानूनी नोटिस भेजा गया था,जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद नोटिस की प्रति संबंधित स्थल पर चस्पा की गई है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

चाकू से केक काटा युवक गिरफ्तार

इंदौर। जन्मदिन पर चाकू से केक काटकर वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो

वायरल होने के बाद कनाड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुमित गिरी नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद युवक थाने में कान पकड़कर अपने कृत्य पर माफी मांगता नजर आया। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में युवक बड़े चाकू से केक काटते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कर जांच शुरू की और उसे हिरासत में ले लिया। एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गलत संदेश देता है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि जन्मदिन या अन्य आयोजनों में हथियारों के प्रदर्शन से बचें और कानून का पालन करें।

अजमेर की युवती युवक से मिलने पहुंची, उसने महिला से हुज्जत की

कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी मल्टी में हाईवोल्टेज ड्रामा

इंदौर। भूरी टेकरी की मल्टी में युवक से मिलने पहुंची युवती के कारण शनिवार रात हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया। आरोप है युवती ने घर में मौजूद महिला से मारपीट की। इसके बाद वह खुद को बेडरूम में बंद कर बैठ गई। मामले में कनाड़िया पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। यहां रहने वाली महिला ने बताया कि शनिवार रात वह अपने पिता के साथ बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान उसके भाई मोहनीश का फोन आया और उसने उन्हें तुरंत घर आने के लिए कहा। घर पहुंचने पर पता चला कि अजमेर निवासी खुशी उर्फ शाइना खान फ्लैट पर आई हुई थी। आरोप है कि उसने घर में मौजूद युवक की मां को कमरे में बंद कर दिया था।

अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जब उनकी मां ने बाहर वालों से बात करने की कोशिश की तो युवती ने उसका मुंह दबा दिया और उनके साथ मारपीट की। परिजनों के मुताबिक जब खुशी से घर छोड़ने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद वह बेडरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंदकर बैठ गई। उसने कथित तौर पर कहा कि वह मोहनीश को नहीं छोड़ेगी और उसे परिवार के लोगों से भी नहीं मिलने देगी। शिकायत में कहा है कि युवती लगातार मोहनीश के साथ रहने की बात कह रही थी। उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि यदि मोहनीश उसके साथ नहीं रहा तो वह आत्महत्या कर लेगी। मामला बढ़ने पर युवती ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खुशी को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली। काफी देर बाद जब मोहनीश फ्लैट से चला गया, तब वह बाहर आई।

बिजली बिल अपडेट करने के बहाने रिटायर्ड जिला पंजीयक से ठगी की

बिजलीकर्मी बताकर दो एप डाउनलोड कराए, खाते से पैसे उड़ाए

इंदौर। शहर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने बिजली बिल का भुगतान अपडेट नहीं होने का झांसा देकर एक रिटायर्ड जिला पंजीयक के बैंक खाते से बड़ी रकम निकाल ली। मामले में कनाड़िया थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार संचार नगर निवासी रमेश कुंभारे जिला पंजीयक कार्यालय से सेवानिवृत्त हैं। 2 जून की रात उनकी पत्नी ज्योति के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने अपना नाम राकेश बताते हुए कहा कि मई माह का बिजली बिल विभाग के अभिलेखों में अपडेट नहीं हुआ है। उसने इसी संबंध में व्हाट्सएप पर संदेश भी भेजा। इसके बाद रमेश कुंभारे ने संबंधित नंबर पर संपर्क कर बताया कि बिजली बिल का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और उसके संदेश भी उनके पास मौजूद हैं। इस पर राकेश ने कहा कि विभागीय प्रणाली में भुगतान दर्ज नहीं दिख रहा है। उसने चेतावनी दी कि यदि भुगतान की जानकारी अपडेट नहीं हुई, तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही उसने दो एप डाउनलोड करने और 12 रुपए का शुल्क जमा कराने की बात कही। आरोपी ने व्हाट्सएप पर एक प्रपोजल भी भेजा। जैसे ही रमेश कुंभारे ने उसे खोला, मोबाइल की स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद हो गई। उन्हें लगा कि तकनीकी कारणों से मोबाइल रुक गया है। कुछ देर बाद मोबाइल बंद कर दोबारा चालू किया गया तो उसमें दो नए ऐप डाउनलोड दिखाई दिए। इसी दौरान उनके मोबाइल पर 24 हजार 500 रुपए निकाले जाने का मैसेज मिला। संदेह होने पर जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जानकारी देखी तो पता चला कि खाते से 25-25 हजार रुपए के तीन लेनदेन, 24 हजार रुपए का एक लेनदेन और 68 हजार रुपए का एक अन्य लेनदेन हो चुका था। ठगी का पता चलते ही उन्होंने पुलिस से शिकायत की। कनाड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल नंबर और बैंक खातों के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मेंटेनेंस विवाद में रहवासी पर हमला, रहवासी सोसाइटी में हड़कंप मचा

छत की चाबी को लेकर शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदली

इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित बिचौली हप्सी के गुलमर्ग परिसर में मेंटेनेंस और छत की चाबी को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। परिसर में रहने वाले तीन युवकों ने एक रहवासी पर डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बी-12 ब्लॉक के फ्लैट नंबर 908 में रहने वाले कार्तिक शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि परिसर में कुछ लोग मेंटेनेंस संबंधी चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान लोकेश जाट कथित रूप से ब्लॉक के रहवासियों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। कार्तिक ने उसे शांत रहने और बिना गाली दिए बात करने की समझाइश दी। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर लोकेश जाट ने अपने साथियों चंदू जाट और सचिन के साथ कार्तिक को घेर लिया। इसके बाद लोकेश और चंदू कार से डंडे निकालकर लाए और कार्तिक पर हमला कर दिया। मारपीट में कार्तिक को हाथ-पैर और शरीर पर चोटें आईं। शोर सुनकर अन्य रहवासी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। कनाड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्नी काम पर गई, पति ने फांसी लगाई, शहर के क्षेत्रों की घटनाएं

इंदौर। लसूड़िया और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सोमवार को खुदकुशी के दो मामले सामने आए। एक मामले में पत्नी काम पर गई तो पति ने फांसी लगा ली। दूसरे मामले में ससुराल में रह रहे युवक ने विवाद के बाद खुदकुशी कर ली। मामला एक राहुल गांधी नगर के विजय रावत (36) ने आत्महत्या कर ली। विजय ड्राइवर था। पत्नी और तीन साल के बेटे के साथ रहता था। घटना के समय पत्नी काम पर गई हुई थी, जबकि बेटा अपनी नानी के घर था। मृतक के भाई आकाश ने बताया कि परिवार में तीन भाई हैं और सभी अलग-अलग रहते हैं। माता-पिता का निधन हो चुका है। शाम को जब पत्नी घर लौटी तो विजय को फंदे पर लटका पाया। परिजनों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया होगा। लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम किया है। दूसरे मामले में पीयूष खटीक (32) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

संपादकीय

मोदी की कार्यशैली से आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनना भी संभव

बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर कुल 4398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। मोदी ने बतौर पीएम 10 जून को 4399 दिन पूरे किए। हालांकि दोनों प्रधानमंत्रियों की यह तुलना अपूर्ण है, क्योंकि नेहरूजी निर्वाचित पीएम से पहले लगभग पांच साल तक देश के मनोनीत प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेहरू के कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड लांघने के लिए मोदीजी को अभी पांच साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। यानी मनोनीत पीएम का कार्यकाल जोड़ दिया जाए तो नेहरू का कुल कार्यकाल 6131 दिन का हो जाएगा। साथ ही इतने लंबे समय तक पीएम रहने वाले वो देश के पहले गैरकांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और संघ की पाठशाला से आए दूसरे प्रधानमंत्री हैं। मोदीजी 75 साल की उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं और अभी एक कार्यकाल और पूरा कर सकते हैं। लेकिन बात यहां केवल कार्यकाल के दिनों की ही नहीं है, मोदी देश के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम और साहसिक फैसले लिए। उन्होंने न केवल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोर एजेंडा पूरा किया बल्कि देश को आगे ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जिसकी वजह से भारत की और खुद मोदी की अलग अंतरराष्ट्रीय छवि बनी। इन फैसलों में उल्लेखनीय हैं डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति, 58 करोड़ जन धन खाते, इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, आयुष्मान भारत के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, हर घर जल और पीएम आवास योजना, ग्रामीण जल जीवन मिश, पीएम आवास योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कड़ा रुख, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भार, उज्ज्वला योजना शामिल है। इनके अलावा अंतरिक्ष और रक्षा-तकनीक में ऐतिहासिक छलांग, जीएसटी और आर्थिक सुधारः वन नेशन, वन टैक्स तथा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथक परिश्रम, लगातार सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना, समयबद्ध काम करना तथा पेशेवर लोगों पर ज्यादा भरोसा करने के लिए जाने जाते थे। मोदी ने देश की राजनीति को भी बदल कर रख दिया है। आजादी के साठ साल बाद समूची राजनीतिक हिंदुत्व केन्द्रित हो गई है। अब कोई भी दल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू समाज को अनदेखा नहीं कर सकता। कमतर नहीं आंक सकता। इस सदी के शुरू तक माना जाता था कि हिंदुत्व की राजनीति से दिल्ली में सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन मोदीजी ने इस मान्यता को उलट दिया है। अपनी कार्यशैली से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब तुष्टीकरण का दौर नहीं चलेगा। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प इसी दिशा में एक कदम है। देश में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण भी मोदी सरकार की संकल्पशक्ति का ही प्रमाण है। इसमें दो राय नहीं कि कई लोग मोदी जी की सोच और कार्यशैली से इत्तफाक नहीं रखते वो भी मोदी के परिश्रम और विजन के कायल हैं। वैसे भी यदि भारत को 21वीं सदी में वैश्विक महाशक्ति बनना है तो उसे आर्थिक और सैनिक महाशक्ति भी बनना होगा। यह काम दमदार और विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के बगैर संभव ही नहीं है। यही कारण है कि मोदीजी ने अपने कार्यकालों के कुछ सालों के बजाए भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का जो महान लक्ष्य सामने रखा है, वो अवश्य पूरा होगा, इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए।

सीमा से तीस्ता तक : भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख चुनावी वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण सबसे प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरे हैं। गौरतलब है कि लंबे समय से केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भारत-बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर चिंता व्यक्त करती रही हैं, जहां से कथित तौर पर अवैध घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा का कारोबार और अन्य सीमा पार आपराधिक गतिविधियां होती रही हैं। नई राज्य सरकार ने जिस सख्ती के साथ इन सब पर लगाम लगाने के लिए जो कदम उठा रही है उससे यह संकेत मिलता है कि वह इन मुद्दों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त और सक्रिय रुख अपनाने जा रही है।

सामरिक और राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक माने जा रहे हैं, लेकिन इन सबको बांग्लादेश में इन्हें लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का रिश्ता केवल पड़ोसी क्षेत्रों का रिश्ता नहीं है। 1947 के बंटवारे और 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद भी दोनों समाजों के बीच सामाजिक और भावनात्मक संबंध बने रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों पर ढाका और बांग्लादेशी समाज की नजर हमेशा बनी रहती है।

नई सरकार ने सरकार गठन के साथ ही कथित अवैध प्रवासियों की पहचान, सत्यापन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीमा को सुरक्षित करने के भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष खुले हिस्सों पर बाड़ लगाने का कार्य भी गति पकड़ रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगने वाली लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण। करीब 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में पहले से बाड़ लगी हुई है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर क्षेत्र अब भी विभिन्न कारणों से खुला है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 27 किलोमीटर भूमि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को हस्तांतरित की है। इसमें 18 किलोमीटर क्षेत्र में सीमा बाड़ का निर्माण और 9 किलोमीटर क्षेत्र में चौकियों, संपर्क सड़कों तथा अन्य सुरक्षा ढांचे का विकास किया जाएगा। आने वाले समय में और भूमि उपलब्ध कराए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ-साथ भारत पिछले कुछ वर्षों में कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ा चुका है। नई सरकार इन उपायों को और व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

सीमा सुरक्षा के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण निर्णय सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की लगभग 120 एकड़ भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक भू-भागों में गिना जाता है। यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा गलियारा है, जो भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और कुछ दूरी पर चीन की सीमा स्थित है। किसी भी सैन्य, सामरिक या आपूर्ति संबंधी संकट की स्थिति में यह क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बन जाता है।

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले एक दशक के दौरान भारत की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि चीन ने दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है। चीन की महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाएं, बंदरगाहों का विकास, ऊर्जा संयंत्रों में निवेश, औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार ने क्षेत्र के कई देशों के साथ उसके संबंधों को गहरा किया है। हालांकि इन परियोजनाओं को औपचारिक रूप से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्रयासों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन नई दिल्ली इन्हें केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं मानती।विशेष रूप से बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों में प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, लालमोनिरहाट क्षेत्र में संभावित हवाई अड्डा विकास और तीस्ता नदी पुर्नस्थापना परियोजना में चीन की रुचि को भारत के सुरक्षा एजेंसियां बेहद संवेदनशील मानती हैं। इसीलिए भारत की आशंका यह रहती है कि आर्थिक निवेश के माध्यम से चीन धीरे-धीरे भारत की सीमाओं के निकट अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। इन्ही सब कारणों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अब केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों को बांग्लादेश में भी एक समान दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। वहां के कुछ राजनीतिक दल, राष्टवादी समूह और नागरिक संगठन इन उपायों को भारत की सख्त सीमा और आव्रजन नीति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे समय में यह मुद्दा और संवेदनशील हो जाता है क्योंकि फरवरी 2026 में सत्ता में आई सरकार पहले से ही कई घरेलू चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में यदि भारत से बड़ी संख्या में लोगों को बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए वापस भेजने की प्रक्रिया तेज होती है, तो यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील विषय बन सकता है। बांग्लादेशी सरकार को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसे एक ओर अपनी जनता की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, तो दूसरी ओर भारत के साथ संबंधों को भी संतुलित बनाए रखना होगा।

बात यहीं नहीं खत्म होती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में यह बहस भी उभर सकती है कि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, उनकी नागरिकता की पहचान और सत्यापन किस आधार पर किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, तो विपक्षी दल इसे सरकार की कमजोरी या कूटनीतिक विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ढाका की आंतरिक राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। सबसे दिलचस्प तो यह है कि बांग्लादेश लंबे समय से यह कहता रहा है कि भारत में मौजूद सभी कथित अवैध बांग्लादेशी वास्तव में बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं। इसलिए वह किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले नागरिकता के ठोस और सत्यापित प्रमाण मांगता है। सोशल मीडिया ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है।

इन सबसे इतर देखें तो यदि भारत-बांग्लादेश संबंधों में किसी एक मुद्दे ने सबसे लंबे समय तक राजनीतिक और कूटनीतिक बहस को जन्म दिया है, तो वह तीस्ता नदी का जल बंटवारा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और तीस्ता सबसे महत्वपूर्ण हैं। सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली तीस्ता नदी उत्तर बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तरी बांग्लादेश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी नदी पर निर्भर है। देश के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक इस नदी के जल पर निर्भर करता है।

बांग्लादेशी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में गजोलडोबा बैराज और अन्य जल परियोजनाओं के कारण सूखे मौसम में नदी का प्रवाह कम हो गया है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि उत्तर बंगाल और सिक्किम की आबादी, कृषि, सिंचाई और जल विद्युत आवश्यकताओं में भी लगातार वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहे प्रभाव ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पहले की तुलना में अधिक अस्थिर बना दिया है।

यहां यह समझने की जरूरत है कि तीस्ता का प्रश्न केवल राजनीति का विषय नहीं है; यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, कृषि, विकास और संसाधन प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। 1983 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम जल बंटवारा व्यवस्था बनी थी, लेकिन वह स्थायी समाधान साबित नहीं हुई। इसके बाद 2011 में एक महत्वपूर्ण समझौते का मसौदा तैयार हुआ था। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार भारत को 42.5 प्रतिशत और बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत जल उपलब्ध कराया जाना था, जबकि शेष हिस्सा पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए रखा जाना था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। राज्य का तर्क था कि नदी में उपलब्ध वास्तविक जल की मात्रा और स्थानीय कृषि जरूरतों का पर्याप्त आकलन किए बिना ऐसा समझौता राज्य के हितों को प्रभावित कर सकता है। यहीं भारत की संघीय व्यवस्था भी इस विवाद के केंद्र में आ जाती है। विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौते केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि जल संसाधन और सिंचाई जैसे विषय राज्यों से जुड़े होते हैं। परिणामस्वरूप नई दिल्ली और कोलकाता के बीच सहमति न बनने के कारण तीस्ता समझौता वर्षों तक लंबित रहा।

आज परिस्थितियां पहले से कुछ अलग दिखाई देती हैं। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच राजनीतिक तालमेल पहले की तुलना में अधिक मजबूत माना जा रहा है। इससे यह उम्मीद पैदा हुई है कि तीस्ता विवाद पर नई बातचीत आगे बढ़ सकती है।

अंकों से आगे का जीवन

युवा मन

डॉ. मनीष जैसल

लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

भारत को दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। देश की बड़ी आबादी युवा है और यही वर्ग आने वाले भारत की दिशा तय करने वाला है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी मानी जाती है, क्योंकि वही विकास, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है। लेकिन आज विडंबना यह है कि यही युवा वर्ग सबसे अधिक मानसिक दबाव, असुरक्षा और भविष्य की चिंता से घिरा हुआ दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और करियर को लेकर जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसने विद्यार्थियों के जीवन को लगातार तनावपूर्ण बना दिया है। आज सफलता को कुछ सीमित पेशों तक बाँध दिया गया है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या बड़ी कॉरपोरेट नौकरी को ही श्रेष्ठ करियर मानने की सोच ने लाखों छात्रों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा दिया है। बच्चों की रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व से अधिक समाज की अपेक्षाएँ महत्वपूर्ण हो गई हैं। यही कारण है कि अनेक विद्यार्थी अपनी पसंद को छोड़कर केवल 'सुरक्षित करियर' की दौड़ में शामिल हो जाते हैं।

स्थिति अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर छात्रों की चिंताएँ भी लगातार बढ़ी हैं। प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षाएँ रद्द होने, परिणामों में देरी और भर्ती प्रक्रियाओं के वर्षों तक लंबित रहने से युवाओं के भीतर निराशा और असुरक्षा की भावना गहराई है। लाखों विद्यार्थी कई वर्षों तक कठिन तैयारी करते हैं, लेकिन जब व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। कई युवाओं को यह महसूस होने लगता है कि उनकी मेहनत का भविष्य अनिश्चित है।

सोशल मीडिया ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। हर दिन दूसरों की उपलब्धियाँ देखकर अनेक छात्र स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं। तुलना की यह संस्कृति धीरे-धीरे मानसिक तनाव को जन्म देती है। विद्यार्थियों में यह डर बढ़ता जा रहा है कि यदि वे किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में पीछे रह गए, तो उनका पूरा भविष्य प्रभावित हो जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अत्यधिक शैक्षणिक दबाव युवाओं को गंभीर मानसिक समस्याओं की ओर धकेल रहा है। बड़ी संख्या में छात्र चिंता, अवसाद, अनिद्रा, माइग्रेन, पैनिक अटैक और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई विद्यार्थियों में सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की भावना भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार पढ़ाई, डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग और असंतुलित दिनचर्या के कारण आँखों की कमजोरी, मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएँ भी सामने आने लगी हैं। दुर्भाग्य से भारत में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की संस्कृति सीमित है। अधिकांश परिवार तनाव और अवसाद को कमजोरी समझ लेते हैं। समस्या की जड़ केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वह सामाजिक मानसिकता भी है जिसने करियर को प्रतिष्ठा और तुलना का विषय बना दिया है। अभिभावक अक्सर बच्चों की रुचि से अधिक समाज की राय को महत्व देने लगते हैं। कई बच्चे कला, खेल, लेखन, संगीत, मीडिया या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बेहतर होते हैं, लेकिन उन्हें पारंपरिक करियर विकल्पों की ओर धकेला जाता है। धीरे-धीरे यह दबाव उनके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित करने लगता है।

जबकि वास्तविकता यह है कि बदलती दुनिया में करियर की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, एनीमेशन, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्किल आधारित अनेक क्षेत्रों में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में तकनीक और कौशल आधारित नौकरियों की मांग और अधिक बढ़ेगी। ऐसे में यदि बच्चों को केवल पारंपरिक विकल्पों तक सीमित रखा जाएगा, तो उनकी प्रतिभा का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। दुनिया के कई देशों ने इस चुनौती को समय रहते समझ लिया। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था इसका बड़ा उदाहरण है। वहाँ बच्चों पर परीक्षा और अंकों का अत्यधिक दबाव नहीं डाला जाता। स्कूल स्तर पर ही विद्यार्थियों की रुचि और व्यक्तित्व को समझने के लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। संगीत, खेल, कला और तकनीकी शिक्षा को समान महत्व दिया जाता है। इसी तरह जर्मनी में 'ड्यूल एजुकेशन सिस्टम' के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवाओं में करियर को लेकर असुरक्षा कम होती है।

भारत में भी नई शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और लचीले करियर विकल्पों पर जोर दिया है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में करियर काउंसलिंग और स्किल आधारित शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन केवल नीतियों से परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसके लिए परिवार और समाज की सोच बदलनी होगी। आज बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें विविध विषयों को पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन, जीवनी और सामाजिक विषयों से जुड़ी पुस्तकें युवाओं के भीतर संवेदनशीलता, तर्क और आत्मविश्वास विकसित करती हैं। कई बार किसी पुस्तक, विचार या अनुभव से ही व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा मिलती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि सफलता केवल ऊँची नौकरी या अधिक वेतन का नाम नहीं है। यदि कोई युवा मानसिक रूप से असंतुष्ट और तनावग्रस्त है, तो ऐसी सफलता अधूरी है। वास्तविक सफलता वही है जिसमें व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट हो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। भारत को यदि अपनी युवा शक्ति को बचाना है, तो शिक्षा और करियर को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को केवल अंकों और रैंक से नहीं आँकना चाहिए। उन्हें अपनी रुचि पहचानने, नए प्रयोग करने और अलग रास्ते चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि दबाव में चुना गया करियर शायद नौकरी दे दे, लेकिन जीवन की शांति और संतुष्टि नहीं दे सकता।

सरकारी क्लीनिक में फर्जी डॉक्टर का हो इलाज

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

यह सर्वज्ञात सत्य है कि सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक में गरीब लोग ही बीमार पड़ने पर ईलाज के लिए जाते हैं। कुछ समय पहले मध्यप्रदेश में सरकारी संजीवनी क्लीनिक खोले गए हैं। यदि इन सरकारी क्लीनिक में डॉक्टर ही फर्जी हो तो मरीज का तो भगवान ही मालिक है! ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश में आया है, जिसमें कुछ फर्जी डॉक्टरों ने फर्जी डिग्री, फर्जी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन या दूसरे डॉक्टरों के पंजीयन नम्बर के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। कुछ ने दूसरे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नम्बर इस्तेमाल कर लिया तो किसी का पंजीयन नम्बर मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं मिला।

यह एक सामान्य परिपाटी है कि सरकारी क्लीनिक हो या ऑफिस हो, उसमें किसी भी पद पर किसी का चयन होता है तो ज्वाईनिंग के समय उनके रिकॉर्ड कासत्यापन किया जाता है। किन्तु यहां सत्यापन ही सही तरीके से नहीं कियागया या जानबूझकर अनदेखा किया गया ! सरकारी संजीवनी क्लीनिक में कुछ फर्जी डॉक्टरों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, जिसे देखकर आश्चर्य और दुख होता है। डॉक्टरी पेशे को ऐसे लोगों ने कलंकित कर दिया है। विदिशा के गंज बासौदा में पदस्थ मुकेश जाटवने डॉ. कुशवेन्द्र सिंह का पंजीयन नम्बर इस्तेमाल कर लिया। मार्कशीट में एक ही फॉन्ट का उपयोग पाया गया है। जाँच में रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट फोटोशॉप से तैयार होना पाया गया। इसी प्रकार आकाश चन्देलकर शिवपुरी में पदस्थ थे। इनके दस्तावेजों की जाँच में पंजीयन नम्बर का जो उपयोग किया गया वह रिकॉर्ड में मिला ही नहीं।

बुद्धमान भिंड में नियुक्त किए गए। जाँच में एमसीआई पंजीयन फर्जी मिला। इसी प्रकार ओंकार सिंह गुर्जर मुरैना में पदस्थ थे। जाँच में इनकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन में एमबीबीएस पास होने का साल 2022 लिखा था, जबकि मार्कशीट और इन्टर्नशिप रिकॉर्ड में 2018-19 पाई गई। जाँच में डिग्री परीक्षा पास करने से 2 साल पहले जारी होना पाई गई। डेढ़ माह की इन्टर्नशिप को 1 वर्ष की जरूरी रोटेटरी इन्टर्नशिप बताया गया। इसी तरह मुरैना के ही हरेन्द्र सिंह दिनकर की मार्कशीट में विषयवार अंकों का योग और कुल

अंक ही मेल नहीं खा रहे। मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं पाया गया।

इसी प्रकार बैतूल के संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ मोनिका सोनी के दस्तावेजों में एमसीआई पंजीयन क्रमांक उनके नाम पर दर्शाया गया, जबकि यह नम्बर डॉ. विभा खुराना का है। गंजबासौदा में पदस्थ मुकेश कुमार ने डॉ. सचिन शिंदे का एमसीआई पंजीयन इस्तेमाल किया। इन महाशय के रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट दोनों एआई की मदद से तैयार होना पाया गया। शिवपुरी में पदस्थ मोहर सिंहका एमबीबीएस में पास होना नवम्बर-दिसम्बर 2018 में बताया गया। डिग्री 20 जनवरी 2018 की जारी दिखाई दी। अर्थात परीक्षा से 10 महीने पहले इनका पास होना पाया गया। इनका रजिस्ट्रेशन नम्बर और कोई रिकॉर्ड ही नहीं पाया गया।

उक्त फर्जी डॉक्टर किस तरह से उनके यहाँ आए मरीजों का इलाज करते थे, इसका भी खुलासा हुआ है। दमोह के सरकारी संजीवनी क्लीनिक की दीवार पर तीन तरह के पर्चे चिपके हुए मिले। इन पर्चों में वजन के हिसाब से बुखार,सर्दी, खाँसी आदि की डोज लिखी पाई गई। हर बीमारी में एक ही तरह की दवा दी जा रही थी। क्लीनिक की दीवार पर चिपके पर्चों में पैरासिटामोल, एमोक्सीसिलिन और सिट्राजिन जैसी दवाईयों का डोज उम्र और वजन के हिसाब लिखी हुई थी। यहाँ पदस्थ फर्जी डॉक्टर सचिन यादव इन्हीं पर्चों को देकरमरीजों का ईलाज करता था। फर्जी डॉक्टरों के विरूद्ध मध्यप्रदेश में जो जाँच की गई। उसकी भनक मिलने पर कुछ डॉक्टर इस्तीफा देकर चले गए और कुछ डॉक्टरों ने क्लीनिक आना ही बंद कर दिया। ऐसे इस्तीफा देने वाले और गायब हो जाने वाले फर्जी डॉक्टरों के दस्तावेजों का भी परीक्षण कर उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए।

राज्य शासन को चाहिए कि गरीबों को सस्ता और सही ईलाज सरकारी संजीवनी क्लीनिक में मिले, इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ डॉक्टरों की डिग्री की जाँच का अभियान शुरू करें। जाँच में दोषी पाए जाने वाले इन फर्जी डॉक्टरों के विरूद्ध न केवल एफआईआर दर्ज की जाए, बल्कि इनके विरूद्ध इंसानों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप भी दर्ज किए जाए। मध्यप्रदेश में संविदा पर भी डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और की गई है। संविदा में पदस्थ डॉक्टर भी फर्जीनहीं मिले, इसके लिए उनके समस्त दस्तावेजों का गहन जाँच की जाए और दोषी पाए जाने पर उन्हें भी सख्त दंड दिया जाना चाहिए। हाल ही में एक अच्छी खबर आई है, वह यह कि राज्य शासन ने प्रदेश में पदस्थ किए जाने वाले संविदा डॉक्टरों के दस्तावेजों, डिग्री आदि के जाँच के आदेश दे दिए है। जाँच को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी संजीवनी क्लीनिक की विश्वसनीयता पर कोई आँच ना आने पाए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कचहरी में एक दिन

व्यंग्य

डॉ.महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पता नहीं कौन सी घड़ी थी,जब हितैषी का नकाब ओढ़े किसी परिचित ने मुझे न्याय मांगने के लिए वकीलों की ओर धकेलते हुए न्यायालय परिसर की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया।मैंने जिस घड़ी वहां कदम रखा, मई के बेरहम सूरज की प्रचंड रश्मियां कॉलेज की लड़कियों की तरह अठखेलियां कर रही थीं। मेरी दोनों कनपटियों से गुप्त गंगा की सहस्त्र धारायें देह को पूर्ण स्नान का अहसास करा रही थीं। सिर पर बाल न होने का दुख जितना जीवन भर सहा,उससे दुगुना इस समय महसूस हो रहा था। जैसे तैसे घबराते चकराते अपना दो पहिया वाहन स्टैंड पर तैनात असभ्य ठेकेदार के लट्ठधारी सभ्य कर्मचारी के हवाले किया और दौड़कर न्याय मंदिर में छलांग मार दी।वहां साहित्य और राजनीति में चर्चित आम आदमी की इतनी रेलमपेल थी कि ग्रीष्मावकाश में रेलवे स्टेशन पर खड़े होने अथवा राजनीतिक दल की रैली में उपस्थित होने का भ्रम हो रहा था। कौन, कब, किसको कुहनी मारकर या धकेल कर, किधर निकल गया किसी की समझ में नहीं आ रहा था।

परिसर की गैलरी के एक ओर काले कोट पर टाई की सफेद पट्टी लटकाये वकीलों की कतार, शिकार की जुगाड़ में प्रतीक्षारत पंक्तिबद्ध बगुलों सी प्रतीत हो रही थी।वे जनप्रतिनिधियों की तरह,पक्षकारों के साथ वक्ता -श्रोता की प्रभावी भूमिका में संलग्न थे। कुछ साथियों की सीटें खाली थीं जो संभवतः काम न होने की वजह से किसी पक्षकार को मुर्गा बनाकर चाय नाश्ते के लिए निकलकर आसपास के झोंपड़ीनुमा होटलों पर चाहे अनचाहे लोगों के साथ देश की दुर्दशा पर गहन मंत्रणा करते हुए अपनी विद्वता के प्रदर्शन में लीन थे।जिनके पास कोई मुर्गा नहीं था वह बार रुम में शतरंज खेलकर या खेलते हुए वकीलों को पल प्रतिपल आवश्यक -अनावश्यक हिदायतें देकर अपनी घड़ियों के कांटे आगे बढ़ाने में जुटे थे। कुछ कैरमबोर्ड के सामने जमे क्वीन कवर को जकड़ने में लगे थे।

कुछ कुर्सियों पर बैठे सहकर्मियों की प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा में किसी नए मुर्गे के हलाल होने की जुगत में प्रतीक्षारत थे। इनमें से कुछ पक्षकारों -दर्शनार्थियों को देखने दिखाने के लिए फाइल उठाकर पन्ने पलटने का नाटक कर रहे थे जैसे कोई ज्योतिषी जातक के सामने उसकी कुण्डली देखते हुए गंभीर मुद्रा में बैठा हो।कुछ नौसिखिए ,मगर होनहार होने का भ्रम पालने वाले घर से लाई हुई तीन-चार फर्जी फाइलों को अपने ही पसीने से तरबतर कांख में दबाये एक कक्ष से दूसरे कक्ष में और पांच मिनिट बाद वहां से निकलकर तीसरे-चैथे कक्ष में घूमकर सीनियर वकील होने का भ्रम फैलाने के प्रयास में लीन थे।कुछ चतुर सुजानों ने विशेष दर्जा लेने के लिए काले कोट की जगह टखनों तक का काला चोगा पहना हुआ था ताकि सीनियर एडव्होकेट होने का संदेश स्वतः प्रसारित हो।

हमारे यहां ग्राम पंचायतों की गंवारु न्याय पद्धति को छोड़कर बिलायती ढंग की न्यायपालिका व्यवस्थित करने में कोट पेंट पहने, टाई लगाने वालों ने अविस्मरणीय योगदान दिया है और यह विराट है कि हम उसी के बोझ से दबे पड़े हैं। कहते हैं काले रंग पर कोई दूसरा रंग अपना असर नहीं छोड़ता पर अधिवक्ताओं पर भारतीय मुद्रा का रंग बहुत गहरा चढता है। न्याय की देवी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है उनके हाथ में तराजू है और पलड़ों में रखे सबूतों के वज़न के आधार पर निर्णय करना है कि दायां वज़नदार या फिर बांया।

इसलिए सभी अधिवक्ता पहले खुद वज़नदार होने का प्रयास करते हैं, उसके बाद प्रकरण को वज़नदार बनाते हैं। न्यायालयों में काम का बोझ ही इतना अधिक है कि बांयी ओर का स्टेनो एक प्रकरण की गवाही लिपिबद्ध करता है तो दांयी ओर का टाइपिस्ट किसी दूसरे वाद की साक्ष्य टंकित करता है। न्यायाधीश के सामने आठ दस वकील अपने प्रकरणों के आवेदन या उनके जबाव देते हुए प्रकरण को समझाने व याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं।उनमें से जो अपनी बारी का इंतजार करते थक जाते हैं वो रीडर को इशारा कर आवेदन फाइल में लगाकर निकल आते हैं।बाहर पक्षकार पूछता है तो वकील साहब कहते हैं- अभी तो सामने वाला वकील जबाव देगा? जिरह होगी,फिर फैसला होगा। जाओ, अगली तारीख पर आ जाना। अगली तारीख यानि- तारीख पर तारीख। क्योंकि कभी छुट्टियां आ जाती है या कभी पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर चला जाता है। कभी किसी का संबंधी शांत हो जाता है तो शोक सभा हो जाती है। नतीजा ढाक के तीन पात। इसलिए हम मानते हैं कि दादा के मुकदमे का निर्णय अगर पोते भी सुन लें तो दादा को मोक्ष मिल जायेगा, भले ही बेटे-बहुओं ने स्वर्ग जाने स्वर्ण-सीढ़ी दान की हो या नहीं। उनकी आत्मा भटकेगी नहीं।

डिजिटल लत

गंगा पाण्डेय
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

सुविधा के जाल में कैद जीवन

डिजिटल लत का अर्थ केवल मोबाइल का अधिक उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति से है जब व्यक्ति तकनीकी उपकरणों और डिजिटल माध्यमों पर इतना निर्भर हो जाए कि उसका दैनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और कार्यक्षमता प्रभावित होने लगे। आज यह समस्या बच्चों, युवाओं, वयस्कों और यहाँ तक कि बुजुर्गों तक में दिखाई देने लगी है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत, बार-बार सोशल मीडिया चेक करना, भोजन करते समय भी स्क्रीन में डूबे रहना और रात को देर तक मोबाइल चलाना डिजिटल निर्भरता के सामान्य संकेत बन चुके हैं। डिजिटल क्रांति ने दुनिया को एक वैश्विक गाँव में बदल दिया है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम ने डिजिटल तकनीक की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट किया।

मानव सभ्यता के इतिहास में तकनीक ने हमेशा जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाने का कार्य किया है। पहिए के आविष्कार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, प्रत्येक तकनीकी उपलब्धि ने मानव जीवन को नई दिशा दी है। किंतु हर आविष्कार के साथ एक चुनौती भी जन्म लेती है। आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहाँ तकनीक केवल एक साधन नहीं रह गई है, बल्कि धीरे-धीरे जीवन का ऐसा हिस्सा बनती जा रही है जिसके बिना अधिकांश लोग स्वयं को अधूरा महसूस करने लगे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने हमारे जीवन को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। यह परिवर्तन जहाँ एक ओर ज्ञान और अवसरों के नए द्वार खोलता है, वहीं दूसरी ओर 'डिजिटल लत' जैसी गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को भी जन्म देता है।

डिजिटल लत का अर्थ केवल मोबाइल का अधिक उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति से है जब व्यक्ति तकनीकी उपकरणों और डिजिटल माध्यमों पर इतना निर्भर हो जाए कि उसका दैनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और कार्यक्षमता प्रभावित होने लगे। आज यह समस्या बच्चों, युवाओं, वयस्कों और यहाँ तक कि बुजुर्गों तक में दिखाई देने लगी है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत, बार-बार सोशल मीडिया चेक करना, भोजन करते समय भी स्क्रीन में डूबे रहना और रात को देर तक मोबाइल चलाना डिजिटल निर्भरता के सामान्य संकेत बन चुके हैं।

डिजिटल क्रांति ने दुनिया को एक वैश्विक गाँव में बदल दिया है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम ने डिजिटल तकनीक की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट किया। किंतु इसी अवधि में स्क्रीन टाइम भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। लोग आवश्यकता से अधिक समय डिजिटल माध्यमों पर बिताने लगे। धीरे-धीरे यह आवश्यकता आदत बनी और आदत कई मामलों में लत का रूप लेने लगी। यही कारण है कि आज डिजिटल लत को एक उभरती हुई वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है।

डिजिटल लत के पीछे कई कारण कार्य करते हैं। सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संरचना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और अन्य मंच ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता अधिक से अधिक समय तक उन पर बना रहे। लाइक, कमेंट, शेयर और नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएँ व्यक्ति के मस्तिष्क में त्वरित संतुष्टि की भावना उत्पन्न करती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन को सक्रिय करती है, जिससे व्यक्ति बार-बार उसी अनुभव को प्राप्त करना चाहता है। परिणामस्वरूप वह अनजाने में घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता है।

डिजिटल लत का सबसे गंभीर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार स्क्रीन के संपर्क में रहने से व्यक्ति की एकाग्रता क्षमता कम होने लगती है। वह किसी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर तुलना की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे हीन भावना, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएँ जन्म लेती हैं। अनेक शोध बताते हैं कि अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाले युवाओं में चिंता, अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी अधिक देखने को मिलती है। डिजिटल दुनिया में मिलने वाली आभासी स्वीकृति वास्तविक जीवन की संतुष्टि का स्थान नहीं ले सकती, किंतु व्यक्ति धीरे-धीरे उसी का अभ्यस्त हो जाता है।

बच्चों और किशोरों पर डिजिटल लत का प्रभाव और भी गहरा है। यह वह अवस्था होती है जब उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा होता है। यदि वे अधिकांश समय मोबाइल गेम, वीडियो या सोशल मीडिया में बिताने लगें, तो उनकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कई बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो जाती है, नींद की समस्या बढ़ती है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। माता-पिता अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने के बजाय मोबाइल में अधिक समय बिताते हैं। यह स्थिति भविष्य में उनके व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

डिजिटल लत का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों में तनाव, सिरदर्द, गर्दन और पीठ दर्द जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की जैविक घड़ी को बाधित करती है, जिससे अनिद्रा और थकान की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

सामाजिक संबंधों पर भी डिजिटल लत का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। परिवार एक साथ बैठा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी-अपनी स्क्रीन में व्यस्त रहता है। बातचीत कम हो रही है और भावनात्मक निकटता घट रही है। मित्रता और रिश्तों का स्थान धीरे-धीरे आभासी संवाद ले रहा है। यह विडंबना ही है कि संचार के साधनों की भरमार के बावजूद लोग पहले से अधिक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया ने हमें जोड़ने का दावा किया था, लेकिन कई बार यह हमें अपने सबसे निकट के लोगों से ही दूर कर देती है।

शिक्षा और कार्यक्षेत्र में भी डिजिटल लत नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है। विद्यार्थी पढ़ाई करते समय बार-बार सोशल मीडिया और मनोरंजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता घटती है। कार्यस्थलों पर भी कर्मचारी अनेक बार मोबाइल नोटिफिकेशन और डिजिटल विचलनों के कारण अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इससे कार्य की गुणवत्ता और दक्षता प्रभावित होती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में गिरावट आधुनिक डिजिटल जीवन की एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

हालाँकि डिजिटल तकनीक स्वयं समस्या नहीं है। समस्या उसके असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग में है। तकनीक एक शक्तिशाली साधन है, जिसका उपयोग ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने, रोजगार सृजित करने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए डिजिटल लत का समाधान तकनीक से दूरी बनाना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलित संबंध स्थापित करना है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए है।

डिजिटल लत से बचने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्क्रीन टाइम के प्रति सजग होना होगा। दिन के कुछ घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना, भोजन के समय फोन का उपयोग न करना, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना और नियमित शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना उपयोगी कदम हो सकते हैं। परिवारों को भी बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उन्हें खेल, पुस्तक-पठन तथा रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ डिजिटल अनुशासन का भी प्रशिक्षण देना चाहिए।

डिजिटल लत केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि मानवीय जीवनशैली से जुड़ा प्रश्न है। यह हमें सोचने के लिए विवश करती है कि क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक हमारा उपयोग कर रही है। आधुनिक जीवन में डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह दूरी संभव नहीं है, किंतु उनके प्रति संतुलित दृष्टिकोण अवश्य अपनाया जा सकता है। वास्तविक जीवन के रिश्ते, प्रकृति का सान्निध्य, पुस्तकों का संसार, संवाद की ऊष्मा और मानवीय संवेदनाएँ किसी भी डिजिटल अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। समय की माँग यही है कि हम तकनीक को अपना सेवक बनाएँ, स्वामी नहीं। तभी डिजिटल युग की उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए हम अपने मानसिक, सामाजिक और मानवीय संतुलन को सुरक्षित रख सकेंगे।

सामयिक

राजेंद्र बज
लेखक स्तंभकार हैं।

युवाओं के मन के इस उबाल को थामना होगा

कॉकरोच जनता पार्टी के हवा में उदय को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। माना कि यह क्षणिक आक्रोश और उत्तेजना का परिणाम है। लेकिन इस तथाकथित दल द्वारा उठाई गई मांगों से अधिकांश नागरिक इत्तेफाक रखते हैं। इस हवाई दल की हवाई परिकल्पना को साकार स्वरूप देने के निमित्त अब उसे एक नया प्लेटफार्म मिल गया है। जिस तरह देश-प्रदेश के मीडिया ने जंतर मंतर के इस प्रदर्शन/आंदोलन को कवरेज किया है, उसके चलते देश का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। यही नहीं अपितु कुछएक विपक्षी दल भी ऐसे आंदोलन का समर्थन करने की मुद्रा में आ गए हैं। जिसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी का नाम जनमानस में तैर गया है।

अब इसका भविष्य क्या होगा ? यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि आने वाले दौर में सही मुद्दों को लेकर युवाओं के अंतर्मन में कुछ न कुछ कौतुक रचने की भावना जागृत होगी। यह स्थिति तमाम स्थापित राजनीतिक दलों के लिए आने वाले समय में एक प्रकार की चुनौती बन सकती है। दरअसल जेन जेड वह पीड़ित भुक्तभोगी समूह है जो कि व्यवस्था की 'व्यवस्था' के प्रति संतुष्ट नहीं है। जो काम सत्तापक्ष को आवश्यक रूप से करना चाहिए और विपक्ष को भी करना चाहिए, उसके प्रति तमाम राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति का अभाव देखा जाता है। यही कारण है कि मजाकिया संगठन उदय में आ रहे हैं और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे जन समर्थन पाने लगे है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। दरअसल यह हवाई संगठन यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर देश के सामने हैं। यह उस व्यवस्था के प्रति मुखर होने का परिचायक है जिसके चलते युवाओं का भविष्य दांव पर लगता जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं यदि आगे जाकर देश के और भी तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर इस संगठन के बैनर तले आम नागरिक एकजुट हो जाएं। वास्तव में देश ने देख लिया है कि लगभग सभी राजनीतिक दल सत्ता को परम लक्ष्य मानकर राजनीति में सक्रिय होते हैं। ऐसे में कौतुक रचने की राजनीति की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित होना बहुत लाजिमी है।

इसलिए देश-प्रदेश में निकट भविष्य में समय-समय पर तमाम तरह के जीव जंतु के नाम पर किसी समूह या संगठन के उदय में आने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। यह स्थिति यह दर्शाती है कि वर्तमान दौर की तमाम तरह की राजनीतिक विसंगतियों और राजनेताओं के आचरण और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर भी एक ऐसा कारण है जिसके चलते सही मुद्दे को लेकर 'कुछ तो भी' संगठन उदय में आने लगे। यह सोचा जाना चाहिए कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बेतुके संगठन की विचारधारा से लोग क्यों जुड़ते जा रहे हैं ? आखिर कौन है जो उसकी मांगों के प्रति असहमत है ?

आश्चर्य का विषय है कि ऐसा संगठन जिसकी वास्तविकता के धरातल पर कहीं से कहीं तक कोई बुनियाद ही नहीं है। जिसका कोई पृथक संविधान नहीं है, कहीं से कहीं तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है और यह एक आक्रोश की ही उपज है। लेकिन इसमें दो मत नहीं कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों में बहुत जान है। इन परिस्थितियों में सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष को आम नागरिकों के हित में अपनी घोषित रीती-नीति को वास्तव में जमीन पर उतार कर दिखाना होगा। अन्यथा समय समय पर वाजिब मुद्दों को लेकर ऐसे बेतुके तथाकथित संगठन की विचारधारा के साथ आम नागरिकों के खड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बीते दौर में अन्ना हजारे के नेतृत्व में व्यवस्था के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया गया था। जिसकी कोख से आम आदमी पार्टी के गठन की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। जिसका कि चुनाव चिन्ह 'झाड़ू' रखा गया। उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग लिया और दिल्ली जैसे क्षेत्र के जागरुक और प्रबुद्ध नागरिकों ने उसे व्यापक समर्थन दिया। नतीजा यह निकला कि देखते ही देखते एक नए राजनीतिक दल का गठन हो गया और वह दिल्ली के सिंहासन पर भी आरूढ़ हो गया। अब यह अलग बात है कि उसका हश्र क्या हुआ ? लेकिन यह एक प्रयोग था, जिसकी ऐसी ही कई पुनरावृत्ति के आसार इस समय बनते नजर आने लगे हैं।

यह तो निश्चित है कि जनभावना के अनुरूप किसी भी प्रकार के संगठन की परिकल्पना जब आकार लेती है, उसके समर्थन में आम जनता खड़ी हो जाती है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के अस्तित्व का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तथाकथित संगठन ने जो सवाल उठाए हैं उससे न केवल युवा वर्ग अपितु अधिकांश पालक/अभिभावक भी इत्तेफाक रखते हैं। जिस वजह से इस परिकल्पना को हवाओं की फिजाओं में उतार दिया गया, अब तक उसके लिए कोई उचित प्लेटफार्म नहीं था। लेकिन जंतर मंतर के प्रदर्शन ने तमाम विपक्षी दलों को बैठे ठाले व्यवस्था के विरोध का एक अच्छा खासा अवसर दे दिया है।

कुत्ताफजीती: अन्तहीन व्यथा-कथा

वक्रोक्ति

मोहन वर्मा
लेखक स्तम्भकार हैं।

कुत्तों का और मनुष्यों का आपसी सम्बंध पौराणिक काल से है। मनुष्यों का कुत्तों से प्रेम जगजाहिर है। कुत्ता कई परिवारों में परिवार के सदस्यों की तरह से रहता आया है। पशु पक्षियों को पालने के मनुष्य के शौक के चलते कई परिवारों में तो कुत्तों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है और परिवार के सदस्यों को कुत्तों की तरह। अगर कहा जाये कि घर परिवारों में कुत्ता फजीती का एक बड़ा कारण यह भी रहा होगा। बात अगर कुत्ता फजीती की,की जाये तो कुत्तों का और मनुष्यों का जितना पुराना नाता है कुत्ताफजीती का इतिहास भी उससे कुछ कम नहीं क्योंकि साथ रहते रहते भी कुत्ते तो मनुष्य नहीं हो पाये मगर मनुष्यों में जरूर कुत्तापन अपनी जगह बनाता रहा और ये सच जगजाहिर भी है। कुत्ते (स्ट्रीट डॉग..वरन डॉग लवर बुरा मान जाएंगे) तो गली मोहल्ले में किसी नये हमजात को देख कर भोंक भांक कर इधर उधर हो जाते है मगर आदमी पर यदि एकबार कुत्तापना हावी हुआ तो वो क्या कर गुजरता है सब जानते है।

कुत्तों के कुत्तापन के किस्से तो यदा-कदा ही सामने आते है कि घरों के सामने रखी गाड़ियों की सीटें फाड़ दी या इसको उसको काट लिया या किसी मासूम को निशाना बना लिया मगर मनुष्यों में कुत्तापन आये दिन देखने को मिलता है। अब कुत्ते तो आखिर कुत्ते हैं.. जानवर.. मगर मनुष्य को तो ईश्वर ने सभी प्राणियों से अलग सोचने समझने की बुद्धि देकर समझदार की श्रेणी में रखा है। वो ही कई बार कुत्तों से ज्यादा कुत्तापन दिखाता है। आए दिन यहां वहां से कुत्ता फजीती की खबरें सामने आती हैं। अभी दो दिन पहले महानगर इंदौर से आई एक खबर के अनुसार कुत्तों को खाना देने के एक छोटे से मामले ने इतना बड़ा तूल पकड़ा कि बुद्धिजीवी कहे जाने वाले राजनीति से जुड़े दर्जनों लोगों ने आपस में जमकर मारपीट और एक दूसरे पक्ष के घरों पर खूब तोड़फोड़ की नतीजा पुलिस रिपोर्ट और कानूनी कार्यवाही तक जा पहुँचा। जिन

कुत्तों के कारण फसाद हुआ उन्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि पढ़े लिखें समझदारों मे फसाद की जड और कुत्ताफजीती में उनकी भूमिका रही है। हालांकि स्ट्रीट डॉग (खालिस कुत्ते) और लाडले पालतू डॉग की दुनिया भी समाज के गरीब और अमीर की तरह ही है। जहां स्ट्रीट डॉग हमेशा गरीब की तरह ही दुत्कारे जाते है वहीं पालतू डॉग्स को अमीरो की तरह हर सुख सुविधा नसीब है। ए.सी कार..हवाई सफर से लेकर विशिष्ट खानपान का आनंद। लाड़,दुलार नर्म बिस्तर पर परिवार के सदस्यों के साथ शयन सुख। जहां गरीब लोग और स्ट्रीट डॉग - (खालिस कुत्ते) हमेशा कुत्ता फजीती का शिकार होकर अपने दुश्मनों से संघर्ष करते रहते है वहीं अमीरों की तरह जिंदगी का आनंद ले रहे पालतू डॉग्स की जिंदगी में कुत्ताफजीती जैसे शब्दों के लिए के लिये कोई जगह ही नहीं होती।

स्ट्रीट डॉग्स के आतंक मचाने पर और नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने पर नगर निगमों का अमला जब नागरिकों को कुत्ताफजीती से राहत दिलाने नींद से जागता है तो कई डॉग लवर्स और पशुप्रेमी संस्थाएं जरूर मोर्चा खोल कर सामने आ जाती है और फिर एक बार ये शाश्वत सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कुत्ताफजीती को लेकर करें तो क्या करें ?

मुद्दा

प्रयाग पाण्डे
लेखक पत्रकार हैं।

अनियंत्रित पर्यटन से त्रस्त है नैनीताल

विश्व विख्यात पहाड़ी हिल स्टेशन नैनीताल में इंसानों से अधिक दोपहिया और चौपहिया वाहनों का रेला उमड़ने लगा है। वाहनों की अनियंत्रित बेतहाशा भीड़ के चलते नगर की सांसें थम- सी गई हैं। अपनी क्षमता से कई गुना अधिक बोझ ढो रही नगर की सभी सड़कें - गलियाँ दोपहिया और चौपहिया वाहनों से पट -सी गई हैं। वाहनों की भीड़ के चलते सामान्य आवागमन बाधित हो गया है। पैदल चलने को रास्ते नहीं बचे हैं। नगर का हरेक कोना और पैदल रास्ते गाड़ियों से पट गए हैं। नगर में यत्र, तत्र, सर्वत्र जाम लगना आम बात हो गई है। नगर का कोई भी कोना यांत्रिक यातायात से निरापद नहीं है। दोपहिया- चौपहिया वाहनों की रेलमपेल में आम इंसान का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पैदल चलने की जगह ही नहीं बची है। इंसानों के भी जाम लगने लगे हैं। पहले पर्यटन सीजन के दिनों कभी-कभार ऐसी स्थिति आती थी, अब यह समस्या बारहमासी हो गई है।

सुंदर प्राकृतिक झील, अनुपम सौंदर्य और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के मद्देनजर 183 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने नैनीताल नगर की बसावट शुरू की थी। औपनिवेशिक शासक नैनीताल की तुलना यूरोपीय देशों से करते थे। नैनीताल का स्वच्छ और शुद्ध वातावरण एवं आबोहवा को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदर्श माना जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में नैनीताल को 'कंट्री रिट्रीट' कहा जाता था। अंग्रेज यहाँ के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का विशेष ख़याल रखते थे। तब नैनीताल की सुंदरता, शांति और सुरक्षा, विश्व विख्यात थी। आज ये सभी खतरे में हैं। वर्तमान में नैनीताल ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के चपेट में है।

नैनीताल की बसासत के प्रारंभिक चरण में यहाँ आने-जाने के लिए रास्तों की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तब कालाढूंगी से पैदल नैनीताल आया जाता था। कालांतर में पुरुषों के लिए घोड़ों की सवारी और महिला यात्रियों के लिए डांडी की व्यवस्था बना ली गई थी। यात्रियों का सामान ढोने के लिए कुलियों का प्रबंध था। करीब चार दशक तक यह व्यवस्था बनी रही। इसी दरम्यान नैनीताल एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में बसा, सजा- सँवरा। उस दौर में मैदानी इलाकों की गर्मियों के थपेड़ों से बचने और विशुद्ध हवा की ठंडी बयार में स्वच्छंद भ्रमण के लिए सैलानी नैनीताल आते थे। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से सर्वथा मुक्त यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक आबोहवा में निष्कंटक पैदल घूमा करते थे।

1862 में नैनीताल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज आगरा एंड अवध की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था। तब भारत के सर्वशक्तिमान ओहदेदार वायसराय, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रांत के आला अंग्रेज अधिकारी समेत सभी कारकुन घोड़े की सवारी अथवा पैदल नैनीताल आया करते थे। 24 अक्टूबर, 1884 को काठगोदाम रेल यातायात से जुड़ गया। इसके बाद यात्रीगण काठगोदाम से ज्योलीकोट-ब्रेबरी होते हुए पैदल नैनीताल पहुँचते थे। कालांतर में ब्रेबरी तक तांगे आने लगे। ब्रेबरी से घोड़ों में बैठकर अथवा पैदल नैनीताल आया जा सकता था। 1893 में नैनीताल तक तांगे पहुँच गए थे। अविभाजित भारत के सबसे बड़े ओहदेदार वॉयसरॉय, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेना और प्रशासन के आला अफसरान तांगों में बैठकर नैनीताल आते थे।

नैनीताल की बसावट के करीब सात दशक बाद 1915 में यहाँ मोटर सड़क पहुँची। तब तक नैनीताल विश्व मानचित्र में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका था। मोटर मार्ग बनने के बाद काठगोदाम से नैनीताल तक मोटर लॉरी चलने लगी थी। नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी मोटर लॉरियों का संचालन करती थी। मोटर लॉरी तल्लीताल तक ही आ सकती थी। 1925 तक नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 88 लॉरियाँ थीं। नैनीताल के लचीले एवं भंगुर पर्यावरण और स्थानीय विशिष्टाओं के मद्देनजर नगर के भीतर यांत्रिक यातायात नहीं था। डांडी, झम्पानी, घोड़े और हाथ रिक्शा ही यातायात के एकमात्र मुख्य साधन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत सभी अंग्रेज हुक्मरान और उनके परिजन नगर के भीतर हाथ रिक्शा और घोड़ों की सवारी किया करते थे। मालरोड और नगर के भीतरी हिस्सों में साइकिल चलाने पर भी सख्त पाबंदी थी। नगर के बाहरी हिस्से में साइकिल चलाने के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। कार्ट रोड (नैनीताल-हल्द्वानी मार्ग) और डिपो रोड (नैनीताल-भवाली मार्ग) में ही साइकिल चलाने की इजाजत दी जाती थी।

1901 में जब नैनीताल की ग्रीष्मकालीन आबादी 7609 थी, सिर्फ 520 बंगले और दूसरे मकानात थे, तभी नैनीताल के भार वहन क्षमता की बात होने लगी थी। अंग्रेज नैनीताल के नाजुक पर्यावरण के मद्देनजर यहाँ निश्चित सीमा से अधिक आबादी को बसाने के सख्त खिलाफ थे। कुमाऊँ के तत्कालीन कमिश्नर कैप्टन ए. डब्ल्यू. इबट्सन ने 19 जुलाई, 1929 को नगर पालिका, नैनीताल की वार्षिक रिपोर्ट में लिखी एक टिप्पणी में कहा था- 'इस समय नैनीताल की एक स्वास्थ्यप्रद नगर की छवि है पर भविष्य में इस छवि को बनाए रखने में कुछ जटिल समस्याएं नज़र आ रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह नगर अति इंसानों से भर गया है।' जब कैप्टन इबट्सन ने यह टिप्पणी की उस दौर में नैनीताल की आबादी करीब बारह हजार थी।

1937 में नगर पालिका ने नैनीताल की मालरोड में नियंत्रित यांत्रिक यातायात की अनुमति प्रदान कर दी। तब नगर पालिका के अध्यक्ष या सचिव की पूर्वानुमति से विशेष परिस्थितियों में तल्लीताल से सचिवालय (वर्तमान उत्तराखंड उच्च न्यायालय) तक ही वाहन आ -जा सकते थे। 1938 में नगर पालिका ने मालरोड में वाहनों की अधिकतम गति सीमा दस मील प्रति घंटा तय कर दी थी। मालरोड में यांत्रिक यातायात की अनुमति दिए हुए दो साल भी नहीं बीते थे भू-वैज्ञानिकों ने मालरोड के अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाहनों की आवाजाही का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के तत्कालीन अधीक्षक ए. एल. कॉल्सन ने 5 अगस्त, 1939 की अपनी एक रिपोर्ट में नैनीताल नगर के भीतर वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा '.......... तल्लीताल से सचिवालय तक गाड़ियां तो जाती हैं। पर इसके अलावा नगर के बाकी इलाकों में वाहनों की आवाजाही पहाड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक है। भारी वाहनों की आवाजाही से नगर की सुरक्षा एवं स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।...... गाड़ी चलाने वालों को खुद पैदल चलकर पदयात्रियों की तकलीफों को महसूस करना चाहिए।' इसके बाद मालरोड में वाहनों की आवाजाही को हतोत्साहित करने की दृष्टि से लेक ब्रिज शुल्क की व्यवस्था की गई। अब यह व्यवस्था नगर पालिका की आमदनी का मुख्य स्रोत बन गई है। 22 जनवरी,1942 को नगर पालिका ने मालरोड में दस पैडल रिक्शे चलाने की अनुमति दी। तब मालरोड में यातायात के नाम पर यही सिर्फ दस पैडल रिक्शे चला करते थे।

1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेज अपने वतन लौट गए। संरक्षणवादी नीतियों को भी वे अपने साथ ले गए। आजादी के करीब दो दशकों तक मामूली शिथिलताओं के साथ ब्रिटिशकालीन व्यवस्थाओं का अक्स बना रहा। उस दौर के जनप्रतिनिधियों ने नगर की सुरक्षा, सुंदरता और शांति के मामले में समझौता नहीं किया। 1960 के दशक में मालरोड में यांत्रिक यातायात नहीं के बराबर था। राजभवन को छोड़कर मालरोड के अलावा नगर के अन्य हिस्सों में गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित था। उस दौर के जनप्रतिनिधियों को मालरोड में एक भी वाहन का गुजरना नामंजूर था। नगर पालिका के तत्कालीन सदस्य चन्द्रलाल साह द्वारा 5 दिसंबर,1966 को बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-दो के जरिए मालरोड में कार और भारी वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने की माँग की थी। यह प्रस्ताव स्थगित हो गया था।

1980 के दशक तक भी नगर में यांत्रिक यातायात नियंत्रित संख्या में था। यहाँ हवाखोरी को आने वाले अधिकांश सैलानी पैदल टहलना पसंद करते थे। देश के शीर्ष राजनेताओं को भी पैदल चलने में संकोच नहीं होता था। वीआईपी कल्चर इस क़दर हावी नहीं था। मारुति संस्कृति आने के बाद नैनीताल का पूरा परिदृश्य बदल गया।

नैनीताल नगर में मोटर मार्ग बाजार क्षेत्र, अश्व मार्ग और पैदल मार्ग सहित सड़कों की कुल लंबाई करीब एक सौ किलोमीटर के आसपास है। इसमें वाहन चालित सड़कों के रूप में मान्य सड़कों की लंबाई करीब 18 किलोमीटर है। बाकी पैदल मार्ग हैं। यहाँ मकानों की संख्या करीब दस हजार के आसपास पहुँच गई है। तकरीबन हरेक परिवार के पास एक से अधिक दोपहिया और चौपहिया वाहन हैं। टैक्सी बाइक और टैक्सी स्कूटी की कोई गिनती ही नहीं है। नगर में टैक्सी बाइक अनगिनत संख्या में निर्बाध रूप से दौड़ रहे हैं। पर्यटक सीजन के दिनों प्रशासन द्वारा निश्चित संख्या में ही पर्यटक वाहनों को नगर में प्रवेश की आज्ञा दी जाती है। बावजूद इसके पीक सीजन में प्रतिदिन करीब ढाई- तीन हजार पर्यटकों के निजी वाहन नैनीताल आते हैं। नतीजतन अब नगर की कोई सड़क, पैदल मार्ग और बटिया दोपहिया और चौपहिया वाहनों से निरापद नहीं है। सभी सड़कों, रास्तों और बाजारों में भी धड़ल्ले से वाहन दौड़ रहे हैं। टैक्सी बाइक, 'पापाज' एवं 'मम्मीज गिफ्ट्स' की भीड़ ने आम लोगों के चलने के लिए सड़कों के किनारों की नालियां भी नहीं छोड़ी हैं। इनकी निरंकुश रफ़्तार के चलते पैदल चलने का अर्थ जीवन को खतरे में डालना हो गया है।

अनियंत्रित, अनियोजित एवं अदूरदर्शी विकास ने स्वप्नलोक को एक अव्यवस्थित और अति भीड़भाड़ वाले नगर में बदल दिया है। इंतजामिया नैनीताल नगर की भार वहन क्षमता का आंकलन कर तदुनुसार गाड़ियों की संख्या नियंत्रित करने के बजाय पार्किंग बनाने पर जोर दे रहे हैं। पार्किंग के लिए नैनीताल में नियम विरुद्ध ब्रिटिशकालीन नालों में लिंटर डाल दिए गए हैं। जिससे नालों का वजूद और औचित्य पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

आज जबकि नैनीताल जैसे हिल स्टेशन में इंसानों के पैदल चलने के लिए जगह नहीं बची हैं, दिन प्रति दिन गाड़ियों की बढ़ती तादाद के लिए आखिर सड़कें आएंगी कहाँ से? जब गाड़ियों के चलने के लिए सड़कें ही नहीं होंगीं, तो पार्किंग बनाने का क्या लाभ? इंतजामिया नैनीताल के अनियंत्रित यातायात को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखता है, हकीकत यह है कि अनियंत्रित एवं अनियोजित पर्यटन नियोजन से जुड़ा विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए नैनीताल की भार- वहन क्षमता का आंकलन कर दूरदर्शी एवं व्यावहारिक पर्यटन नीति बनाने की आवश्यकता है। फिलवक्त इस ओर सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। नतीजतन आज नैनीताल अपनी बेनूरी और दुर्दशा पर सिसक रहा है।

जनपद पंचायत कार्यालय में खरीफ सीजन को लेकर उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा

सोहागपुर । कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जनपद पंचायत कार्यालय में सोहागपुर अनुविभाग की खरीफ सीजन के दृष्टिगत खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की बैठक अनुविभागीय अधिकारी सुश्री प्रियंका भलावी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस

अवसर पर जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल,जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पटेल,कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।बैठक में समितियों एवं डबल लॉक केंद्रों पर उपलब्ध उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं एवं सुझावों पर अपने विचार व्यक्त किए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए ।एसडीएम प्रियंका भलावी ने बताया कि अनुविभाग क्षेत्र में वर्तमान में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। आपने किसानों से अपील की कि वे ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से अग्रिम रूप से ई-टोकन बुक कर खाद प्राप्त करें। तथा अपनी सुविधा अनुसार निकटतम समिति से खाद का उठाव करें। इससे किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा एवं भीड़भाड़ से बचने में सुविधा होगी। बैठक में खाद वितरण व्यवस्था को सुचारु एवं पारदर्शी बनाए रखने तथा किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

व्यर्थ जल बर्बाद न हो सार्वजनिक नलों में टोंटियां लगाएं, नपा में बैठक संपन्न

सोहागपुर । नगर पंचायत परिषद कार्यालय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री धर्मेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में समस्त पंप चालकों एवं वार्ड प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर के सभी वार्डों में नर्मदा जल योजना एवं नगर पालिका पाइपलाइन के माध्यम से प्रदाय किए जा रहे पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि जिन घरों में नर्मदा जल योजना एवं पुरानी नगर पालिका पाइपलाइन दोनों के नल कनेक्शन लगे हुए हैं। उनमें से पुरानी नगर पालिका के नल कनेक्शन नियमानुसार विच्छेदित किए जाएं। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के यहां नर्मदा जल योजना के एक से अधिक कनेक्शन हैं तथा वे अतिरिक्त कनेक्शन हटवाना चाहते हैं। उनके अतिरिक्त कनेक्शनों को भी नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए। बैठक में निर्देश दिया गया कि जिन वार्डों में सार्वजनिक नलों पर टोंटियां नहीं लगी हैं। वहां शीघ्र टोंटियां लगाई जाएं ।ताकि जल की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसे घरों एवं क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जहां नर्मदा जल योजना का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। जिससे आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सके ।मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री धर्मेंद्र शर्मा ने सभी पंप चालकों से जल प्रदाय व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को नियमित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण जिम्मेदारी एवं तत्परता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान उपयंत्री श्री बृजेश खानोरकर, प्रभारी राजस्व निरीक्षक संजय परसाई सहित समस्त पंप चालक उपस्थित रहे।

रेत के अवैध भंडारण पर 13 लाख 31 हजार 250 की अर्थदण्ड राशि की प्रस्तावित

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण के प्रकरण में खनिज विभाग ने 13 लाख 31 हजार 250 की अर्थदण्ड राशि की प्रस्तावित की है। विदित है कि 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई थी, जिसमें अवैध भण्डारणकर्ता चंद्रकांत पिता प्रशांत मंडल, निवासी फुलबेरिया तहसील घोड़ाडोंगरी के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के नियम 18 (2) के तहत कार्यवाही करते हुए कुल राशि 13, 31, 250 की शास्ति प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व के वर्षों में भी घोड़ाडोंगरी और शाहपुर क्षेत्र में रेत के अवैध भण्डारण पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई है। उक्त क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2023 में कुल 03 प्रकरण, वर्ष 2024 में कुल 21 प्रकरण, वर्ष 2025 में कुल 03 प्रकरण दर्ज किए जाकर निराकरण के लिए न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किए गए थे।

कुंडी में अवैध सागौन परिवहन पर वन विभाग की कार्रवाई

9 सागौन लट्ठों से भरा ट्रैक्टर जब्त, वन अपराध प्रकरण दर्ज

भौंरा। उत्तर वन मंडल बैतूल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सारणी के ग्राम कुंडी में वन विभाग ने अवैध सागौन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सागौन लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। संयुक्त वन अमले की इस कार्रवाई में 9 सागौन लट्ठे बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30 से 35 हजार रुपये बताई जा रही है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कुंडी क्षेत्र में सागौन लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र भौंरा एवं वन परिक्षेत्र सारणी के संयुक्त वन अमले ने कार्रवाई करते हुए संतोष एवं मनीराम निवासी कुंडी के खेत के पास एक ट्रैक्टर को रोककर जांच की। जांच में ट्रैक्टर में सागौन के 9 लट्ठे पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। वन विभाग के अनुसार जब्त सागौन लकड़ी का कुल आयतन 0.705 घन मीटर है। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर एवं लकड़ी को वन परिक्षेत्र भौंरा कार्यालय लाया गया। इसके उपरांत वन परिक्षेत्र सारणी में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जब्त वाहन को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए सारणी ले जाया गया। भौंरा रेंजर विजेंद्र तिवारी ने बताया कि अवैध सागौन परिवहन की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सारणी वन परिक्षेत्र अधिकारी शरदेन्दु नायक ने बताया मामले में वन अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा लकड़ी के स्रोत एवं परिवहन से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। कार्रवाई में डिप्टी रेंजर मूलशंकर पारते सहित अमित तिवारी, सौरव सिरोठिया, संतोष कावरे, विनय तिवारी एवं वन विभाग का अन्य अमला शामिल रहा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा के अवैध दोहन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा

बैतूल। स्थानीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के तहत नगर पालिका एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 कार्य की समीक्षा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में प्रेक्षक शशि भूषण सिंह सेवानिवृत्ति आईएस ने जिले की नगरीय एवं ग्रामीण निकायों में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों ने निकायवार पुनरीक्षण कार्य प्रगति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। प्रेक्षक श्री सिंह ने निकायवार वार्डों की संख्या, कुल मतदाताओं की स्थिति, नवमतदाताओं के पंजीयन, नाम विलोपन, संशोधन तथा प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने दावे एवं आपत्तियों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल होना तथा अपात्र नामों का नियमानुसार विलोपन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड पर रहने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर वंदना जाट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, एसडीएम, तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद सीईओ उपस्थित थे।

हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी को सेवा का माध्यम मानकर कार्य करें : कांतदेव सिंह

संगठनात्मक आगामी कार्यक्रमों को लेकर भाजपा की जिला बैठक संपन्न

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कामकाजी मासिक बैठक जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभागीय संगठन प्रभारी कांतदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष संगठन की कार्य योजनाओं को धरातल पर मजबूती से लाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। इस जिम्मेदारी को हमें सेवा का माध्यम मानकर पूरा करना है। श्री कांतदेव ने मासिक बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और संगठन की कार्ययोजनाओं को धरातल पर मजबूती से उतारने को लेकर विस्तृत चर्चा की। संगठन की प्रगति और सेवा के संकल्प के साथ निरंतर अग्रसर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित किया। बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि देश के जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की सफलता आज के कालखण्ड में आवश्यक है। श्री उइके ने कहा कि विपक्ष में जो किरदार है वे नकारात्मक उर्जा के साथ व्यवहार कर रहे है। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार ने कहा कि मोदी जी के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐतिहासिक कार्यों और योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रमों के तहत पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे अभियानों को भी गति दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार हमारे ऊर्जावान और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। श्री पवार ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ 21 जून तक होने वाले सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों के को लेकर घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं के साथ हितग्राहियों के बीच संपर्क करना है और सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। बैठक का संचालन 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अभियान के जिला संयोजक कृष्णा गायकी ने किया एवं अंत में आभार जिला टोली के सदस्य देवीसिंह ठाकुर ने व्यक्त किया। जिले की मासिक बैठक में विधायक चंद्रशेखर देशमुख, डा.योगेश पंडाग्रे, गंगा उइके मंचासीन रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और मोर्चो के जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे।

प्रायोगिक प्रशिक्षण से दूर होंगी शिक्षकों की कठिनाईयां, 230 ने सीखे प्रयोग

बैतूल। सीमेट (भोपाल) द्वारा जिला अंतर्गत समस्त हायर सेकेंडरी स्कूलों के भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान शिक्षकों हेतु तीन दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 8 से 10 जून 2026 तक यह आयोजन बैतूल बाजार स्थित शासकीय सांदीपनि कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। दो चरणों के इस प्रशिक्षण में कुल 230 शिक्षकों ने भाग लिया। यह आयोजन डाइट प्रभात पट्टन की प्राचार्या सरिता आंडे के नेतृत्व और प्रशिक्षण प्रभारी श्रीमती शबीना बेग की सक्रिय भूमिका में संपन्न हुआ। मेजबान विद्यालय के प्राचार्य आर. के. मालवीय ने सामग्रियां उपलब्ध कराई तथा विज्ञान प्रभारी सविता महाले ने प्रयोगशालाओं का प्रबंधन संभाला। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स राकेश खातरकर, धनराज कहार, आशुनाथ साहू, शिवानंद पाटिल, डॉ. सतीश कुमार साहू व मनोज बुवाडे ने प्रयोगों को सरल रूप में सिखाया। भौतिकी शिक्षक रविकांत आर्य ने बताया कि इससे उपकरणों को संयोजित करना व परिणाम शुद्ध लाना आसान होगा। जीव विज्ञान शिक्षक घनश्याम वरवड़े एवं अभय जोशी ने बताया कि सत्र में मानव कंकाल, सूक्ष्मदर्शी, समसूत्री विभाजन और ब्लड ग्रुप का प्रयोग सिखाया गया। रसायन शिक्षक उमेश शर्मा ने बताया कि मास्टर टैनर श्री खातरकर एवं श्री कहार द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ, प्रेरणादायक व उपयोगी रहा। साल में एक बार ऐसा आयोजन अवश्य होना चाहिए ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हों। रसायन शिक्षक शिवकुमार मन्सुरिया और विनोद बारमासे के अनुसार भी यह सत्र बेहद रोचक रहा।

सोनखेड़ी में आज से देवी भागवत कथा

4 जून को पीताम्बरा सहस्त्रनाम महायज्ञ

बैतूल। मुलताई क्षेत्र के ग्राम सोनखेड़ी में 11 जून से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा रसपान एवं श्री मां पीताम्बरा सहस्त्रनाम महायज्ञ का आयोजन शुरू होगा। 11 से 13 जून तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा वाचन एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन मां बगलामुखी सिद्ध साधिका एवं संत गुरु माता मां देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी द्वारा किया जाएगा। आचार्य रविन्द्र मानकर ने बताया कि 11 जून को भव्य कलश यात्रा, गुरु वंदना एवं आदिशक्ति प्राकट्य की कथा के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा। 12 जून को नवदुर्गा, दशमहाविद्या और चौंसठ योगिनियों की महिमा का वर्णन किया जाएगा, जबकि 13 जून को भक्त चरित्र, देवी कृपा प्रसंग, महाआरती एवं कथा विश्राम होगा। 14 जून को श्री मां पीताम्बरा सहस्त्रनाम महायज्ञ एवं माँ बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार क्षेत्र के अनेक गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। धार्मिक आयोजन के बाद 15 जून को दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क त्रिकालदर्शी मां बगलामुखी दिव्य दरबार आयोजित किया जाएगा, जहां श्रद्धालु अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उपस्थित हो सकेंगे। इस आयोजन के यजमान नारायण दवण्डे एवं प्रमिला दवण्डे हैं। समिति सदस्य वासुदेव ताडगे ने क्षेत्रवासियों से सपरिवार उपस्थित होकर कथा, यज्ञ, महाप्रसादी एवं दिव्य दरबार का लाभ लेने की अपील की है। आयोजन समिति के अनुसार सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और पूरे क्षेत्र में श्रद्धा व उत्साह का माहौल है।

नगर पालिका ने कमानी गेट से गोठाना रोड तक हटाया अतिक्रमण

हर बुधवार चलेगा विशेष अभियान

बैतूल। शहर को व्यवस्थित, सुंदर और जाममुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने और पात्र हितग्राहियों के पुनर्व्यवस्थापन का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत बुधवार को कमानी गेट से गोठाना रोड तक फैले अतिक्रमणों पर संयुक्त कार्रवाई की गई। नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अमले ने मिलकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नगर पालिका के अनुसार शहर में फैले बेतरतीब अतिक्रमणों को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक बुधवार को अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। पूर्व में अतिक्रमणकर्ताओं से शपथ-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया कि संबंधित व्यक्ति बैतूल का स्थायी निवासी हो, उसका समग्र आईडी और आधार कार्ड स्थानीय हो तथा उसकी अन्यत्र कोई दुकान संचालित न हो। इस प्रक्रिया में कुल 565 हितग्राहियों ने अपने प्रमाण-पत्र नगर पालिका को प्रस्तुत किए थे। नगर पालिका अब इन्हीं 565 पात्र हितग्राहियों को शहर के पांच निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित करने की कार्रवाई कर रही है। इसके तहत नंदी चौक के सामने फल बाजार विकसित किया जाएगा, जबकि ज्योति टॉकीज के सामने, कांतीशिवा टॉकीज के पास, अभिनंदन सरोवर के पास तथा कारगिल चौक के समीप अन्य हितग्राहियों को व्यवस्थित किया जाएगा। बुधवार को कमानी गेट से गोठाना रोड तक की गई कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम, बसों एवं अन्य वाहनों के आवागमन में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। स्थानीय नागरिकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अतिक्रमण हटाने एवं व्यवस्थित करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस अभियान में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग नगर पालिका को प्राप्त होगा।

एनसीटीई पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण का आवंटन जारी

● विद्यार्थियों को 15 जून तक जमा करना होगा प्रवेश शुल्क

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु संचालित ई-प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एनसीटीई पाठ्यक्रमों (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. आदि) के प्रथम चरण का महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण में पात्र अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये 15 जून 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 64,641 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 59,113 आवेदनों का सत्यापन किया गया। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने लॉगिन के माध्यम से आवंटन की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा में शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटन निरस्त माना जाएगा तथा सीट आगामी चरणों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 11 जून को नई दिल्ली में

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 11 जून को नई दिल्ली में होने जा रही है। बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकासरखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल एक साथ मिलकर समावेशी मानव विकास प्रारूप पर चर्चा करेंगे। बैठक मुख्यतः मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण एवं सभी के लिए समानता और गरिमा से जुड़े विषयों पर केन्द्रित रहेगी। बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

पानी के विवाद से खुला मामला, दो भाइयों पर 'पॉक्सो' में केस

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में गंभीर आरोपों में बदल गया। पुलिस ने रामानंद नगर निवासी दीपक कुमावत और उसका भाई रोशन पर दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि सोमवार को वह इलाके में पानी भर रही थी। इसी दौरान रोशन ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घर पहुंचकर उसने पूरी घटना अपने पिता को बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता आरोपियों से बात करने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। परिजनों को आरोप है कि दीपक लंबे समय से उस पर गलत नजर रखता था। आने-जाने के दौरान उसका पीछा कर कई बार बातचीत करने का दबाव भी बनाता था। पीड़िता ने कहा कि नौकरी के दौरान भी आरोपी उसके संपर्क में आने की कोशिश करता था।

बच्ची से गलत हरकत का आरोप - मामले की जांच के दौरान एक और गंभीर आरोप सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के मकान में रहने वाले किराएदार की 12 वर्षीय बेटी के साथ भी दीपक ने अश्लील हरकत की थी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने बच्ची को थाने बुलाकर पूछताछ कर उसके बयान दर्ज किए। प्राथमिक जांच में दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट तथा रोशन पर अभद्रता और विवाद करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

पोल शिफ्टिंग के चलते आज बंद रहेगी बिजली

बैतूल। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 11 जून को कारगिल चौक से गाढ़ाघाट रोड तक निर्माणाधीन सड़क में बाधा बन रहे विद्युत पोलों को शिफ्ट किया जाएगा। जिसके चलते 11 केव्ही इटारसी रोड फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल जोन -2 के प्रबंधक ने बताया कि गुरुवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फॉरेस्ट नाका, इटारसी रोड, गाड़ाघाट रोड, बालाजी विहार, बसंत पेट्रोल पंप, सेमल वाले बाबा, मारुति शोरूम आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन की सख्त कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में ग्राम डोंगरवाडा, तहसील नर्मदापुरम में प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान 03 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए गए, जिन्हें मौके पर जप्त कर पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम की अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बिजली कंपनी द्वारा शिविर लगाकर किया जा रहा बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण

सीहोर (निप्र)। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महाप्रबंधक श्रीमती पूनम तुमराम ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद कर उन्हें त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है। विद्युत वितरण केन्द्रवार बनाए गये कलस्टरों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की बिल, मीटर, सर्विस केबल, कनेक्शन एवं तकनीकी सेवाओं संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 08 जून को सीहोर संभाग अंतर्गत ग्राम जमोनिया तालाब, शिकारपुर, मुस्करा, पडली, सीहोर शहर के वार्ड 19, वार्ड 10 एवं आष्टा संभाग अंतर्गत ग्राम शेखुखेड़ा, बेदाखेड़ी, आष्टा शहर के वार्ड नं. 08, ग्राम किल्लोद में शिविर लगाकर बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया।अभियान के अंतर्गत 09 जून को आष्टा संभाग अंतर्गत ग्राम रसूलपुरा, चाचरसी, बर्छापुरा तथा 10 जून को ग्राम लौरासखुर्द, करमनखेड़ी, सेंधोखेड़ी, आष्टा शहर वार्ड नं. 10, बड़लिया बरामद, एवं सीहोर संभाग अंतर्गत छापरी तालिका, आमलारामजीपुरा, नयापुरा, बरखेड़ाकुर्मी, सेमलीजदीद में शिविर लगाए जाएंगे।

जिला स्तरीय मलेरिया एलिमिनेशन टास्क फोर्स समिति की बैठक सह कार्यशाला आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में मलेरिया निरोधक जिला स्तरीय मलेरिया एलिमिनेशन टास्क फोर्स समिति की बैठक एवं अंतर्विभागीय कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में वर्षा ऋतु को देखते हुए डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि मच्छर जनित रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें सभी विभागों और आमजन की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि 'डेंगू नियंत्रण सबकी चिंता, सबकी भागीदारी और सबकी जिम्मेदारी' के साथ व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान जलभराव वाले स्थानों की नियमित निगरानी की जाए तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। नगर पालिका एवं पंचायत विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में साफ-सफाई, जल निकासी और लार्वा नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में कहा गया कि स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को डेंगू-मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए तथा रैली, पोस्टर प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विद्यार्थियों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया जाए। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजागरूकता को अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया जाए। सोशल मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, पोस्टर, पंपलेट और माइकिंग के माध्यम से आमजन तक बचाव संबंधी संदेश पहुंचाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर लोगों को बुखार आने पर तुरंत जांच एवं उपचार कराने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि मलेरिया निरोधक माह के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें तथा प्रत्येक गांव और वार्ड तक जागरूकता गतिविधियां पहुंचाई जाएं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि फीवर सर्वे, लार्वा सर्वे और रोग नियंत्रण संबंधी सभी गतिविधियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती क्षमा बर्वे ने डेंगू मलेरिया नियंत्रण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

वर्षा ऋतु से पूर्व नपा प्रशासन अलर्ट मोड पर

जिले को जलभराव से मुक्त रखने युद्ध स्तर पर चल रहा नालों-नालियों की सफाई एवं गहरीकरण अभियान

नर्मदापुरम (निप्र)। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए शहर में जलभराव एवं जल निकासी संबंधी समस्याओं से नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जिले भर में नगरीय प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष सफाई एवं गहरीकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के सख्त एवं स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में नगर पालिका अमला पूरी सक्रियता और मुस्तैदी के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।

कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानसून प्रारंभ होने से पूर्व सभी छोटे-बड़े बरसाती नालों एवं नालियों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उनके निर्देशों के बाद नगर पालिका की टीमें लगातार मैदानी स्तर पर निरीक्षण एवं सफाई कार्य में जुटी हुई हैं।

नगर पालिका प्रशासन द्वारा विशेष रूप से उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां पूर्व वर्षों में जलभराव की समस्या सामने आई थी। ऐसे संवेदनशील इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर नालों की सफाई, गहरीकरण एवं अवरोध हटाने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत नालों में जमी गाद, प्लास्टिक, पॉलीथिन एवं अन्य ठोस अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

सफाई कार्य में मैन्युअल तरीके के साथ-साथ आधुनिक मशीनों एवं संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य आवश्यक उपकरणों के माध्यम से बड़े नालों का गहरीकरण कराया जा रहा है, जिससे वर्षा जल की निकासी तेजी एवं सुचारू रूप से हो सके। इससे सड़कों, बाजार क्षेत्रों एवं रिहायशी इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याओं में काफी हद तक कमी आएगी।

नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही सफाई कार्यों की निरंतर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि मानसून के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे नालियों एवं नालों में प्लास्टिक, घरेलू कचरा अथवा अन्य अपशिष्ट सामग्री न फेंकें। नागरिकों के सहयोग से ही शहर की स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। नगरीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा जहां कहीं भी जल निकासी में बाधा पाए जाने की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिले में 28 जून से 30 जून तक पांच वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलिया की दवा

रायसेन (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिले में 28 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे पल्स पोलियो अभियान के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पल्स पोलियो की जिला टास्क फोर्स की बैठक तथा कार्यशाला सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि जिले में 28 जून से 30 जून तक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिले में कोई भी पात्र बच्चा पोलियों की खुराक से छूटे नहीं, इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। बैठक में टीकाकरण अधिकारी डॉ सोमनदास ने बताया गया कि जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 184000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य है। इसमें 28 जून 2026 को जिलेभर में स्थापित पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की खुराक पिलाई जाएगी। इसके पश्चात 29 एवं 30 जून 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

मेरा युवा भारत के एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम अंतर्गत युवाओं ने किया तितली पार्क एवं वन क्षेत्र का भ्रमण

रायसेन (निप्र)। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, रायसेन द्वारा संचालित एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम के तहत युवाओं का शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण तितली पार्क तथा वन क्षेत्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सामान्य वन मंडल रायसेन के सहयोग से किया गया।

भ्रमण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि वन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों, पक्षियों, तितलियों एवं वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तितली पार्क में युवाओं ने विभिन्न प्रजातियों की तितलियों, औषधीय एवं स्थानीय वनस्पतियों का अवलोकन किया तथा उनके संरक्षण के महत्व को समझा।

इस अवसर पर युवाओं को जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरणीय शिक्षा को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ना तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। युवाओं ने इस भ्रमण को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा आयोजित यह एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम युवाओं को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे उनमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो रहा है।

शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थी 20 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कान्हा शांतिवनम हैदराबाद हुए रवाना

बैतूल (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय हार्टफुलनेस फाउन्डेशन एवं शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल के बीच हुए एमओयू के अनुसरण में 8 जून को संस्था के फ्लोरीकल्चर एण्ड लैंडस्केपिंग के 41 प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय प्रशिक्षक श्री दिलीप बेले एवं कु. प्रतिमा गौरे के नेतृत्व मे 20 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग कान्हा शांतिवनम हैदराबाद रवाना हुए।

रवाना होने पूर्व बैतूल रेलवे स्टेशन पर हार्टफुलनेस संस्था के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह परिहार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामना देते हुए ऑन जॉब ट्रेनिंग मे मन लगाकर कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कान्हा शांतिवनम विश्व के सबसे बड़े ध्यान एवं आध्यात्मिक परिसरों में से एक है जहां विशाल उद्यान, हरित क्षेत्र, पौधों की विविध प्रजातियां तथा आधुनिक लैंडस्केपिंग की उत्कृष्ट व्यवस्था विकसित की गई है।

फ्लोरीकल्चर एण्ड लैंडस्केपिंग ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को उद्यान प्रबंधन, पौध उत्पादन , पौध संरक्षण तथा आधुनिक लैंडस्केप डिजाइनिंग से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। साथ ही हार्टफुलनेस ध्यान की विधि सीखने का अवसर प्राप्त होगा।

संस्था प्राचार्य श्री अजीश पंद्रे ने बताया कि ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल पर अनुभव प्रदान करती है, जिससे उनके तकनीकी कौशल के साथ-साथ कार्य संस्कृति, टीम वर्क एवं व्यवसायिक दक्षता का भी विकास होता है। उन्होंने बताया कि हार्टफुलनेस फाउंडेशन से हुए एमओयू के तहत संस्था में सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 5 दिवसीय ध्यान शिविर आयोजित किए जा रहे है एवं विशेष रूप से फ्लोरीकल्चर एण्ड लैंडस्केपिंग व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों को हार्टफुलनेस संस्था के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कान्हा शांतिवनम फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस में 20 दिवसीय निःशुल्क ऑन जॉब ट्रेनिंग विगत 3 वर्षों से प्रदान की गई। इसी अनुक्रम में इस वर्ष के 41 प्रशिक्षणार्थियों को कान्हा वनम् भेजा गया है। जहां ऑन जॉब ट्रेनिंग पश्चात चयनित प्रशिक्षणार्थियो को हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के रूप मे जॉब भी प्रदान की जाएगी।

पात्र बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी योजना से वंचित न रहे और सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं - कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में आज जिला स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांस्बा, सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन , लाभान्वित बालिकाओं की संख्या तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने निर्देश दिए कि योजना के पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से लाभ उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र बालिका लाड़ली लक्ष्मी योजना से वंचित न रहे।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत उन बालिकाओं के प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिनका पंजीयन अभी तक नहीं हो सका है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे सभी प्रकरणों का सत्यापन कर पात्रता अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

बैठक में शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित सभी बालिकाओं की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन की जाए। साथ ही बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खुलवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित एवं सशक्त बनाना है। इसलिए सभी अधिकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, जिससे अधिक से अधिक पात्र बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।

नियत शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर चार स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

विदिशा (निप्र)। स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में शिकायतें सही पाए जाने पर चार स्टाम्प विक्रेताओं की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं।

वरिष्ठ जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन ने बताया है कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा द्वारा नगर विदिशा क्षेत्र में जांच की गई। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि शपथ-पत्र बनवाने के लिए स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जा रही थी। जबकि मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 के नियम-11 के अंतर्गत दस्तावेज लेखन एवं संबंधित कार्यों के लिए शुल्क स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ स्टाम्प विक्रेता नियमों के विपरीत कार्य कर आमजन से अतिरिक्त धनराशि वसूल रहे थे। इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टाम्प विक्रेता श्री मोकमसिंह पंथी, श्री पवन कुमार सुमन, श्री सुब्रत राज जैन एवं श्री रियाज कुरैशी की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन है और ऐसी शिकायतें मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी दस्तावेज या शपथ-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगे जाने पर इसकी सूचना संबंधित राजस्व अधिकारियों को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जनकल्याण शिविरों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, योजनाओं में सैचुरेशन के साथ लंबित जनसमस्याओं का प्राथमिकता से करें निराकरण : कलेक्टर डॉ सोनवणे

कलेक्टर ने समयसीमा बैठक में दिए निर्देश, 12 से 18 जून तक आयोजित होंगे जनकल्याण शिविर

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को आयोजित समयसीमा बैठक में 12 जून से 18 जून तक आयोजित होने वाले जनकल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविरों का प्रभावी ढंग से आयोजन कर हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से छूटे पात्र लोगों को लाभान्वित करने के साथ-साथ आमजन की लंबित समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने निर्देश दिए कि रास्ता विवाद, राशन पर्ची, फिंगरप्रिंट नहीं मिलने से आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याएं, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, 5 वर्ष से कम बच्चों के आधार कार्ड जैसी समस्याओं से संबंधित लोगों की सूची तैयार कर पात्रतानुसार शिविरों में लाभ दिलाया जाए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने को कहा।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के ऐसे क्षेत्रों, जहां मोबाइल टावर होने के बावजूद नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, वहां नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल को निर्देशित किया। उन्होंने वन एवं राजस्व विभाग को समन्वय बनाकर बीएसएनएल के जमीन आवंटन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने को कहा। दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों के लिए सभी ब्लॉकों में मेडिकल बोर्ड आयोजित करने तथा शिविरों में विभागीय

प्रदर्शनी लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनकल्याण शिविरों के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम नोडल अधिकारी रहेंगे तथा जनपद सीईओ एवं सीएमओ सहायक नोडल रहेंगे।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने 5 जून से 21 जून तक विशेष पर्यावरण अभियान के तहत स्वच्छता, पौधरोपण एवं जनजागरूकता गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जनजातीय बालक आश्रम डोडाजाम में मिली शौचालयों की खराब स्थिति मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागों को कार्यालयों, स्कूलों एवं छात्रावासों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने नगरीय निकायों एवं जनपदों में स्वच्छता, पेयजल, रोशनी एवं उद्यानों की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों की फोटो एवं नाम कार्यालयों में प्रदर्शित कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग को स्कूलों में फर्स्ट एड किट एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों की सफाई एवं गहरीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए जनपदवार मॉनिटरिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने शिविरों के दौरान शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में श्रम, स्कूल शिक्षा, वाणिज्यकर तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को विशेष फोकस के साथ प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। वहीं भैंसदेही, आठनेर, भीमपुर एवं चिचोली जनपदों को शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने लोक सेवा गारंटी एवं समयसीमा प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण, कंट्रोल रूम के प्रभावी संचालन तथा पंचायत स्तर पर स्कूल, आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर कम प्रगति वाले जनपदों को कार्य में तेजी लाने को कहा। साथ ही प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कम व्यय होने पर भैंसदेही एवं भीमपुर जनपदों के सीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जबलपुर-दमोह में ओले गिरे, 18 जिलों में आंधी-बारिश

खजुराहो 46 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा बालाघाट में बारिश, 16 जिलों में भी अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं। बुधवार को बालाघाट में दोपहर करीब साढ़े 3 बजे तेज बारिश हुई। वहीं, पिछले 24 घंटे के दौरान जबलपुर और दमोह में ओले गिरे। भिंड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सतना और मऊगंज जिले में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई है। सिंगरौली और नरसिंहपुर में धूलभरी आंधी भी चली। मौसम विभाग के अनुसार, जबलपुर में सबसे ज्यादा 74 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चली। सीधी में 68 किमी, सागर में 59 किमी, ग्वालियर में 46 किमी, आगर-मालवा में 44 किमी, अशोकनगर में 43 किमी, रीवा में 37 किमी, गुना में 35 किमी, शिवपुरी में 33 किमी और शहडोल में हवा की रफ्तार 30 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई।

इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में बारिश का अलर्ट है। वहीं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गर्मी का असर रह सकता है।

12 जून को लू नहीं, ओले गिरने का अलर्ट

मौसम केंद्र भोपाल ने पहले 10 और 11 जून को प्रदेश के 5 जिले भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया था, लेकिन मंगलवार को जारी हुए ताजा फोरकास्ट में लू ही जगह ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो 12 जून को मुरैना, भिंड, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओले गिर सकते हैं। वहीं, प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तेज आंधी के साथ बारिश होगी।

शरीर में धंसी थीं तीन गोलियां, फिर भी आतंकी को मार गिराया

शौर्य चक्र लेकर लौटे सीआरपीएफ कमांडो का रीवा में ग्रैंड वेलकम

रीवा (नप्र)। राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र लेकर लौटे विंध्य के लाल का रीवा रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ है। सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी ने खुद तीन गोली खाकर आतंकियों को मार गिराया था। इस बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र मिला है। इससे विंध्य समेत पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ा है।

सिरमौर के डेल्ही गांव निवासी हैं संजय- दरअसल, सिरमौर तहसील के डेल्ही गांव निवासी सीआरपीएफ कमांडो संजय दिल्ली से शौर्य चक्र लेकर लौटे तो रीवा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग ढोल नगाड़े के साथ उमड़ पड़े। ढोल-नगाड़ों की थाप, फूल-मालाओं और भारत माता की जय के नारों के साथ विंध्य के इस लाल का जोरदार अभिनंदन किया गया है। पूरा रेलवे स्टेशन भक्तिमय नारों से गूंज रहा था।

अपनी जान से ज्यादा प्यारा है देश

शौर्यपूर्ण अभियान को याद करते हुए कमांडो संजय तिवारी ने कहा कि उनके लिए अपनी जान से ज्यादा अपना देश प्यारा है। उन्होंने बताया कि उन्हें तीन गोलियां लगी थीं, लेकिन उन्हें अपनी चोटों की चिंता नहीं थी। उनके लिए सबसे जरूरी था कि आतंकी बचकर न निकल पाए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि आतंकवादी को मार गिराना उनका परम कर्तव्य था।

जम्मू-कश्मीर में किया था ऑपरेशन

संजय तिवारी को यह सर्वोच्च सम्मान उनके असाधारण साहस और कर्तव्य परायणता के लिए दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उनकी टीम को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भारी गोलीबारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच संजय तिवारी अग्रिम हमला दल का हिस्सा बनकर आगे बढ़ते रहे। सीआरपीएफ कमांडो ने कहा आतंकियों की भर्ती करने वाले पाकिस्तानी आतंकी उस्मान लाहौरी को शॉर्ट इनफॉरमेशन पर हमलोगों ने ढेर किया था। वह टारगेट कीलिंग में भी शामिल था।

लश्कर के आतंकी को मार गिराया

मुठभेड़ के दौरान उनके बांह, घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों में तीन गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई जारी रखी। साथ ही लश्कर के आतंकी को मार गिराया।

बिजली उपभोक्ताओं को अलर्ट- फर्जी मैसेज और कॉल के जरिए हो रही ठगी

- साइबर जालसाजों से सावधान रहें, बिल भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करें

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के सम्माननीय बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का नगद भुगतान कंपनी के जोन, वितरण केन्द्र कार्यालय, पीओएस मशीन अथवा अधिकृत भुगतान केन्द्रों जैसे एम.पी.ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर पर ही करें। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के केशलेस भुगतान हेतु कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप, व्हाट्सएप पे एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से भी बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उपभोक्ता को असमय विद्युत विच्छेदन से बचने हेतु किसी निजी मोबाईल नंबर से कॉल कर भुगतान करने हेतु कोई एसएमएस/ व्हाट्सएप जारी नहीं किया जाता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एसएमएस केवल सीसीएमपीसीजेड (CCM-PCZ) एवं व्हाट्सएप केवल 07552551222 सेंडर आईडी से ही प्रेषित किए जाते हैं। उपभोक्ता किसी अन्य सेंडर आईडी अथवा निजी नंबर से आए भ्रामक मेसेज से सतर्क रहें। कंपनी अंतर्गत विद्युत देयकों के भुगतान के लिए उपभोक्ता पहचान नंबर यानि आईवीआरएस नंबर की जरूरत होती है। आईवीआरएस नंबर के आधार पर ही जोन, वितरण केन्द्रों या अन्य गेटवे एमपी ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे. अमेजन पे, व्हाट्सएप पे आदि पर बिजली बिलों का भुगतान होता है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से आए फोन या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर किसी भी मोबाइल नंबर पर देयकों की राशि अंतरित न करें। साथ ही अपना पिन नंबर भी किसी के साथ साझा न करें। कंपनी के संज्ञान में आया है कि सायबर जालसाजों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज अथवा आई.व्ही.आर. तकनीक से फोन कॉल पर नंबर दबाने हेतु कहा जाता है जिसमें बिल भुगतान कराने हेतु भय बनाकर कि आपकी बिजली कुछ घंटों बाद काट दी जाएगी, इसके लिए बिल भुगतान करने हेतु विशेष नंबर दबाएं, मोबाइल नंबर विशेष अथवा अनजान लिंक/एप पर क्लिक कर या संपर्क कर बकाया राशि जमा कराएं। इस प्रकार के एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज एवं आई.व्ही.आर. फोन कॉल फर्जी हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है इस प्रकार के फर्जी सायबर जालसाजों से सतर्क और सावधान रहें। साइबर फॉड संबंधित किसी भी घटना की सूचना तत्काल भारत सरकार की हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराए ।

दिल्ली मेट्रो में सफर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में सफर किया।

सीएम मोहन यादव बोले

'कांग्रेसियों ने ही मीनाक्षी नटराजन का खेल बिगाड़ा

उस सीट पर कई नेताओं की थी नजर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यसभा चुनाव में 'सीट चोरी' के आरोपों को नकारते हुए बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का 'खेल बिगाड़ने' का काम उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया क्योंकि उनमें से कई की नजर उस सीट पर थी। राज्यसभा की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया, जब शपथपत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया।

कांग्रेस ने जानबूझकर की यह गलती- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 'जानबूझकर' और 'षड्यंत्रपूर्वक' नटराजन के फॉर्म में गलतियां कीं। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब सीट नहीं मिली तो नटराजन का खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने ही कर दिया।

नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं ने जताई नाराजगी

- हमारे नेताओं ने विधायकों की बेइज्जती करवा दी, हम बहुत दुखी हैं

कांग्रेस विधायकों का प्लेन रनवे से लौट गया है। इसके बाद कांग्रेस के एक विधायक का गुस्सा फूट पड़ा है। एयरपोर्ट से बाहर लौटते वक्त वह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति गुस्से से लाल था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे नेताओं ने विधायकों की बेइज्जती करवा दी है।

विधायकों के बेंगलुरु शिफ्ट कर रही थी कांग्रेस- दरअसल, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर रही थी। विधायकों को लेकर जाने के लिए प्लेन आ गई थी। कांग्रेस विधायक बेंगलुरु में पिकनिक मनाने की तैयारी में थे। कांग्रेस विधायक परिवार के साथ वहां जा रहे थे। सभी विधायक प्लेन में जाकर बैठ गए। प्लेन बेंगलुरु ले लिए उड़ान भरने वाली थी। रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कैंसिल हुआ तो विधायकों से भरे प्लेन को रनवे से लौटना पड़ा।

फूट पड़ा विधायक का गुस्सा- बेंगलुरु टूर कैंसिल होने के बाद हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारे नेताओं की भी बहुत बड़ी गलती है। ये सब चीजें इतनी जल्दी करवाने की जरूरत क्या थी। आपको इतनी जल्दी क्या थी। दो दिन रुकने के बाद सब प्लान करना चाहिए था। पहले से जगाकर सामने वाले को मौका दिया और उन्होंने नुकसान कर दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा बेइज्जती करने के सिवा कुछ और नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं ने हम विधायकों की बेइज्जती की है। बीजेपी ने भी की है।

बड़े नेताओं ने बेइज्जती की- उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हमारी बेइज्जती की है। हमें गुस्सा है। पार्टी कार्यकर्ता और विधायक जमीन पर लड़ते हैं और यहां इस तरह की हरकतें होती हैं। तीन दिन से चल रहीं हरकतें ठीक नहीं हैं। ये सब प्लान से हुआ है। प्लेन रनवे पर चल गया और लौटा दिया गया।

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के भोपाल जिला अध्यक्ष नियुक्त

भोपाल। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन जनाब हाफिज़ अहमद शाहमीरी खुर्रम चिश्ती साहब के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जनाब ओसाफ अली बबलू को ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का भोपाल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त भोपाल जिला अध्यक्ष जनाब ओसाफ अली बबलू ने हज़रत डॉ. ओसाफ शाहमीरी खुर्रम मियाँ चिश्ती साहब के व्यक्तित्व, सेवाओं एवं समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

गुना में दबंगई की सारी हदें पार

अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां ले उड़े रसूखदार, रोकने पर दी जान से मारने की धमकी

गुना (नप्र)। जिले में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला और बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बमोरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिलावटी रामपुरा में दबंगों ने श्मशान की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से एक मृतक की अंत्येष्टि के बाद उसके अवशेष चोरी कर लिए। घटना से आक्रोशित और दुखी परिजन मंगलवार को तीसरे की रस्म के दिन अस्थियां न मिलने पर सीधे कलेक्टोरेट पहुंचे और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।

चिता की राख के अलावा कुछ नहीं मिला- मंगलवार को जब परिवार के लोग तीसरे की प्रथा के लिए श्मशान पहुंचे तो वहां चिता की राख के अलावा कुछ नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि सिलावटी रामपुरा पंचायत की यह श्मशान भूमि बेहद पुरानी है, जिस पर करीब तीन किलोमीटर दूर पांचौरा गांव के कुछ रसूखदार आरोपी जबरन कब्जा कर मकान बनाना चाहते हैं।

अस्थियां चोरी

मिली जानकारी के अनुसार, सिलावटी रामपुरा निवासी दीवान सिंह राजपूत का बीती 7 जून को निधन हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने सुबह करीब 7 बजे स्थानीय श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया था। मृतक के साले गुलाब सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार के अगले दिन रात के वक्त दूसरे गांव पांचौरा के रहने वाले श्याम मीना, लक्ष्मण मीना, मुरारी मीना, विलदास, घनश्याम लोधा और ओमप्रकाश लोधा सहित अन्य लोग श्मशान पहुंचे और वहां से चिता के सारे अवशेष और अस्थियां चोरी कर ले गए।

नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

- शव के पास मिला मोबाइल, कमरे में मिलीं गर्भनिरोधक गोलियां, पिता बोले- हमने फोन नहीं दिलाया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में 17 साल की एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे की है। पुलिस को मौके से एक मोबाइल फोन और गर्भनिरोधक गोलियों का पत्ता मिला है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी। वह अपने पिता के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां 2017 से अलग रह रही है। परिवार में उससे छोटा एक भाई और एक बहन हैं।

कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो हुई जानकारी- घटना के समय दोनों छोटे भाई-बहन घर के बाहर खेल रहे थे। रात में घर लौटने पर उन्होंने बहन को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने अपने चाचा को सूचना दी। चाचा ने छात्रा के पिता को बुलाया। पिता के घर पहुंचने पर दरवाजे में बने छेद से अंदर देखा गया। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई।

पिता ने कहा- मोबाइल हमनें नहीं दिलाया- पिता का कहना है कि उन्होंने बेटी को कभी मोबाइल फोन नहीं दिलाया था। घटनास्थल के पास एक मोबाइल मिला है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कमरे से गर्भनिरोधक गोलियों का पत्ता भी मिला है। उनका कहना है कि ये सामान घर में कैसे आया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गृहग्राम और ससुराल में नहीं रह सकेंगे पंचायत सचिव

नई तबादला नीति जारी, रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बने तो भी हटाए जाएंगे

भोपाल (नप्र)। तबादला सीजन के बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई नीति के तहत अब कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम या ससुराल की पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही जिस पंचायत में सचिव के रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएंगे, वहां से भी सचिव का तबादला किया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आधार पर यह नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं।

15 जून तक होंगे तबादले

9 जून को जारी आदेश के अनुसार 15 जून तक जिले के भीतर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया एक जून से ही मान्य की जाएगी। विभागीय निर्देशों के मुताबिक स्थानांतरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे। नई गाइडलाइन में जिला एवं अंतरजिला स्तर पर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तय की गई है।

सरकार को इसलिए रखनी पड़ी शर्त

दिग्विजय सरकार ने वर्ष 1994 से 1996 के बीच पंचायत कर्मियों की नियुक्ति की थी, जो आज पंचायत सचिव हैं। तब नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से की गई थी और ज्यादातर मामलों में ग्राम सभा ने सरपंच, उप सरपंच, पंच या गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदारों को नियुक्त किया था। ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि ये जनप्रतिनिधि रिश्तेदारी या अहसान के बदले सचिवों को वह सब करने के लिए राजी कर लेते हैं, जो वे चाहते हैं। ऐसे कई मामले जांच में आ चुके हैं। जिनमें सरपंच, उप सरपंच और सचिव ने मिलकर गड़बड़ी की है। इसलिए सरकार को तबादला नीति में यह शर्तें जोड़नी पड़ीं।

इन परिस्थितियों में स्थानांतरण होगा अनिवार्य

विभाग ने कुछ मामलों में ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण अनिवार्य किया है, जिनमें इस तरह की परिस्थितियां शामिल हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का रिश्तेदार पंचायत का सरपंच या उपसरपंच चुन लिया गया हो।

सचिव को उसके पैतृक ग्राम या ससुराल स्थित ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा।

जो सचिव एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। यदि 10 साल या अधिक समय से पदस्थ सचिवों की संख्या तबादला लिमिट से अधिक है तो पहले सबसे अधिक अवधि से पदस्थ सचिव का तबादला किया जाएगा।

प्रतिबंध अवधि में भी संभव होगा इनका स्थानांतरण

स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में इन सचिवों के तबादले किए जा सकेंगे।

भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या गंभीर शिकायतों के मामले।

अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने की स्थिति।

लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू अथवा अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़े प्रकरण।

उच्च प्राथमिकता वाले प्रशासनिक मामलों में शासन स्तर से प्राप्त निर्देश।

ऐसे मामलों में विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद आयुक्त, संचालक पंचायत राज द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।